आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650

इंदौर, बुधवार 17 दिसंबर 2025

■ वर्ष : 5 ■ अंक : 44

■ पृष्ठ : 6 ■ मूल्य : 2

सांध्य दैनिक

इंदौर संकेत

dainikindoresanket.com
dainikindoresanket
dainikindoresanket
dainikindoresanket24@gmail.com

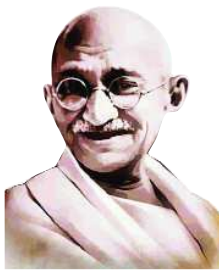

राष्ट्रपिता को नमन...

अंदर के पन्नों पर...

तीन कन्फेंक्शनरी यूनिट में प्रदूषण बोर्ड ने की कार्रवाई

पेज-2

मां हमेशा हौसला देती थी : पारुल

पेज-5

चोइथराम ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों की शुरू होगी जांच

पेज-6

न्यूज ब्रीफ

- 'यह मामला गांधी परिवार को सताने के लिए....', नेशनल हेराल्ड केस पर बोले खड़गे
- गोवा अग्निकांड के आरोपियों लूथरा ब्रदर्स को आज दिल्ली से गोवा लाएगी पुलिस
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग पर आज मेरठ बंद का ऐलान
- दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन से संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई
- आज भारत आ सकते हैं अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर नूर जलाल जलाली
- भोपाल : आज आयोजित किया जाएगा मप्र विधानसभा का एक दिवसीय सत्र
- हैदराबाद : पंचायत चुनावों का तीसरा और अंतिम चरण के लिए आज होगा मतदान
- अभिषेक बनर्जी आज अस्वस्थ सांसदों के साथ करेंगे बैठक, आंतरिक मतभेदों को लेकर होगी चर्चा
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 3 की जिंदा जलकर मौत, 1 घायल
- देश के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर, पहाड़ों पर बर्फ... मैदानों में कोहरा

स्वच्छ शहर की आबोहवा हुई प्रदूषित

वाहनों और निर्माण कार्यों की बढ़ती रफ्तार से तेजी से बढ़ रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • राष्ट्रीय पुरस्कारों और साफ-सुथरी सड़कों के बल पर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक के रूप में इंदौर की छवि अब सर्दियों के दौरान बढ़ते प्रदूषण से चुनौती का सामना कर रही है। शहर की स्वच्छता की प्रशंसा तो जारी है, लेकिन हर गुजरते सप्ताह के साथ इसकी हवा और भी प्रदूषित होती जा रही है।

तेजी से हो रहे शहरी विकास ने इंदौर को एक विशाल निर्माण क्षेत्र में बदल दिया है। इसके 276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 200 से अधिक निर्माण स्थल सक्रिय हैं। साथ ही, छह फ्लाईओवरों के निर्माण के साथ-साथ मेट्रो निर्माण, सीवर लाइन और पाइपलाइन परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। इन सभी गतिविधियों के कारण धूल से भरे बड़े-बड़े इलाके बन गए हैं। मलबे, टूटी सड़कों और खुले निर्माण क्षेत्रों से उड़ने वाली धूल वाहनों की बढ़ती संख्या से निकलने वाले धुएं के साथ मिल जाती है। यह मिश्रण चुपचाप शहर के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहा है, जो आधिकारिक वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है।

छोटी ग्वालटोली स्थित प्रदूषण निगरानी केंद्र इंदौर में वास्तविक वायु प्रदूषण का एकमात्र सटीक संकेतक बनकर उभरा है। रेलवे स्टेशन, सरवते बस स्टैंड और कई व्यस्त यातायात गलियारों के चौराहे पर स्थित यह केंद्र लाखों लोगों द्वारा प्रतिदिन साँस के माध्यम से ग्रहण किए जाने वाले वास्तविक उत्सर्जन और धूल के भार को मापता है। नवंबर के लगभग आधे महीने तक यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब श्रेणी में रहा, और दिसंबर के पहले पखवाड़े में लगातार 110 के पार रहा, तथा 11 से 13 दिसंबर तक लगातार तीन दिनों तक 200 के पार बना रहा। इंदौर के एक्यूआई नेटवर्क में आठ चालू स्टेशन हैं (सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार), लेकिन इनमें से अधिकांश मेघदूत गार्डन, रेजिडेंसी और रीजनल पार्क जैसे बगीचों या हरे-भरे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां वायु गुणवत्ता में कणों का स्तर स्वाभाविक रूप से कम होता है। रीजनल पार्क में स्थित दो स्टेशनों में से एक कई महीनों से काम नहीं कर रहा है, जबकि अन्य स्टेशन भी कभी भी खराब हो जाते हैं, जिससे शहर की निगरानी क्षमता और कमजोर हो जाती है। केवल दो स्टेशन ही वास्तव में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। एयरपोर्ट स्टेशन को टर्मिनल क्षेत्र से हटाकर हरियाली से घिरी पहाड़ी पर स्थित बिजासन टेकरी में स्थानांतरित करने से शहर भर में प्रदूषण के स्तर में और भी कमी आई, जिससे निर्माण कार्य की धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं के वास्तविक प्रभाव को छिपाया जा सका।

एक्यूआई में अंतर: समर बनाम एक्यूआई

शहर में प्रदूषण की स्थिति प्लेटफॉर्म के अनुसार तेजी से बदलती है। सीपीसीबी की आधिकारिक निगरानी प्रणाली समर ऐप पर, 15 दिसंबर को शहर का एक्यूआई 89 था, जो एयरपोर्ट (81) और रीजनल पार्क (45) जैसे हरित क्षेत्र के स्टेशनों के कारण कम था। छह स्टेशनों में से केवल तीन ही सक्रिय थे, जिनमें से केवल एक ही प्रदूषित स्थल छोटी ग्वालटोली था, जिसका एक्यूआई 142 था।

राजनीतिक अटकलें : प्रियंका गांधी की प्रशांत किशोर से सीक्रेट मिटिंग

नई दिल्ली (एजेंसी) • चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में जन सूरज पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं में लौट आए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीके ने हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जिससे राजनीतिक हलकों में नई अटकलें लगने लगी हैं। बैठक लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें दोनों ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तर भारतीय राज्यों के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की।

हालांकि दोनों पक्षों ने प्रियंका गांधी और पीके की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताकर इसके राजनीतिक अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। लेकिन राजनीतिक रूप से यह मुलाकात काफी दिलचस्प है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में प्रशांत किशोर और कांग्रेस का रिश्ता कड़वाहट भरा रहा है। प्रशांत किशोर ने 2021 में जद(यू) से निष्कासित होने के एक साल बाद कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव दिया था। उनकी 2022 में कांग्रेस आलाकमान के साथ बातचीत शुरू हुई। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के 10 जनपथ निवास पर प्रशांत किशोर ने राहुल और प्रियंका सहित शीर्ष नेतृत्व के सामने पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर के प्रस्तावों पर विचार के लिए एक पैनल गठित किया। कुछ दिनों बाद सोनिया ने कांग्रेस की राजनीतिक चुनौतियों के लिए 'एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप' बनाया और किशोर को इसमें शामिल होने का न्योता दिया। लेकिन किशोर ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वह इस ग्रुप में सिर्फ सदस्य बनकर शामिल होने के बजाय अधिक अधिकार और स्वतंत्रता चाहते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन देखने वाले जी-23 समूह के सदस्य भी शामिल थे, उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति के इशारे पर पार्टी संगठन में बदलने का विरोध किया।

सहारा सिटी में लगाए पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • देवगुराड़िया बायपास रोड स्थित सहारा सिटी क्षेत्र में पिछले तीन दिन से घूम रहे तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया है। रालामंडल रेस्क्यू टीम ने क्षेत्र में दो पिंजरे लगाए थे। मंगलवार रात पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया। माना जा रहा है कि बीती रात शिकार की तलाश में तेंदुआ पिंजरे तक पहुंचा था।

डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि इस क्षेत्र में तेंदुए के पंजों के निशान मिलने के बाद उसके मूवमेंट की पुष्टि हो गई थी। इसके बाद वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा था। क्षेत्रवासियों से भी आए दिन तेंदुए के दिखने की सूचनाएं मिल रही थीं, जिसे देखते हुए सोमवार शाम को पिंजरा लगाया गया और आसपास की कॉलोनियों के रहवासियों को सतर्क किया गया था। डीएफओ ने बताया कि 85 एकड़ की सहारा सिटी के आसपास घना जंगल है। यहां नीलगाय सहित अन्य वन्यप्राणियों का मूवमेंट रहता है।

तेंदुआ के साथ शावक भी

स्थानीय रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र में तेंदुए के साथ उसके दो शावकों का भी मूवमेंट देखा गया है। वन विभाग अब इस आशंका को ध्यान में रखते हुए आसपास के इलाके में सर्चिंग और निगरानी बढ़ा रहा है। फिलहाल पकड़े गए तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी की जा रही है।

अब सरवटे और गंगवाल कहलाएंगे सिटी बस टर्मिनल

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • शहर की वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यातायात जाम है, जिसके निराकरण के लिए यह प्रयास किया जा रहा कि शहर की सड़कों से वाहनों को कैसे कम किया जाए, जिस पर लंबे समय से मंथन चल रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन गादव ने इंदौर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा की ओर से एक प्रजेंटेशन दिया गया, जिसमें इंदौर शहर के को बाहर कर वर्तमान बस स्टैंड का उपयोग सिटी बस टर्मिनल के रूप में करने की प्लानिंग की गई है। वर्मा के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सराहा और लागू करने के निर्देश भी दिए हैं।

शहर में चार स्टैंड से चल रही बसें : प्रयास यह किया जा रहा है कि शहर की सभी बसें कुमेड़ी और नायता मुंडला बस स्टैंड से चलाई जाएं। वर्तमान में बसें सरवटे, तीन इमली और गंगवाल बस स्टैंड से संचालित की जा रही है। मह, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम सहित अन्य उपनगरों को आने-जाने वाली बसें कई बार फेरे लगाती है, जिससे शहर में यातायात गंभीर रूप से प्रभावित होता है।

बड़े नेताओं की सिफारिशों को एडजस्ट करने की कवायद के बीच घोषित हुई जिला इकाई

श्रवण चावड़ा ने अपने पीए को बनवा दिया सह कार्यालय मंत्री

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • इंदौर बीजेपी के बड़े नेताओं की आपसी टसल में उलझी बीजेपी ग्रामीण जिला कमेटी आखिरकार कल घोषित की गई। इसमें मंत्री तुलसी सिलावट खासे भारी पड़े हैं और अपने कई समर्थकों को उन्होंने जगह दिलवाई है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक उषा ठाकुर के समर्थकों को भी तवज्जो मिली है। लेकिन मनोज पटेल के समर्थक इतनी जगह नहीं पा सके हैं। कारण है कि जिलाध्यक्ष श्रवण चावड़ा भी खुद देपालपुर से हैं, ऐसे में उन्होंने भी अपने करीबियों को जगह दी है।

महामंत्री के तीन अहम पद इनके समर्थक : महामंत्री पद पर अंतदयाल है। इनका नाम ग्रामीण जिलाध्यक्ष के लिए मंत्री सिलावट ने बढ़ाया था लेकिन तब बात नहीं बनी तो अब महामंत्री पद पर समायोजन हुआ है। रामस्वरूप गेहलोत भी महामंत्री बने हैं जो राउ विधायक मधु वर्मा के करीबी है और विधानसभा संयोजक भी रहे हैं। यह श्रवण चावड़ा के भी करीबी है।

अंतर दयाल और गेहलोत दोनों ही कलौता समाज से आते हैं। वहीं तीसरे महामंत्री पूंजालाल निनामा है, जो पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं। संघ पृष्ठभूमि से भी है और विधायक उषा ठाकुर के करीबी है और एसटी वर्ग से हैं।

उपाध्यक्ष पद के लिए कौन किसका समर्थक : उपाध्यक्ष बनाए गए भारत सिंह चौहान सांवेर से हैं और सिलावट के करीबी है। दिलीप चौधरी भी सांवेर के हैं और सिलावट के ही करीबी है। विनोद जाट मानपुर के होकर सांसद कविता पाटीदार के करीबी है। लीला संतोष पाटीदार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की करीबी है।

कल देर रात परदेशीपुरा के टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • शिवाजी नगर इलाके में कल देर रात एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कच्चा माल, कपड़ा और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

फायर ब्रिगेड को रात करीब 11 बजे भावना टेक्सटाइल्स नाम की फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फैक्ट्री में आग तेजी से फैल चुकी थी, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को करीब तीन घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान लगभग 20 हजार लीटर पानी का इस्तेमाल कर आग को पूरी तरह बुझाया गया। फैक्ट्री भावना जैन की है। आग की सूचना मिलने पर जैन परिवार के सदस्य भी देर रात मौके पर पहुंचे। घटना के समय फैक्ट्री में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, क्योंकि रात में सभी कर्मचारी फैक्ट्री से जा चुके थे। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले की जांच जारी है।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर कर्मियों के अनुसार आग में फैक्ट्री में रखा कच्चा मटेरियल, कपड़ा और अन्य जरूरी सामान जल गया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है।

शेष बचे 15 दिन... साल 2025 की यादें होगी ताजा 'दैनिक इंदौर संकेत' के साथ

इंदौर • दैनिक इंदौर संकेत। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय महाराजा यशवंत राव होलकर अस्पताल में हुई एक घटना ने पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया। नवजात शिशुओं के एनआईसीयू में चूहों ने दो नवजात शिशुओं के हाथ कुतर दिए थे। इस घटना ने देश-प्रदेश में इंदौर के अस्पतालों की छवि को आघात पहुंचाया। घटना के बाद भी अस्पताल प्रबंधन आगामी कार्रवाई को लेकर गंभीर नजर नही आया था।

जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के 122 दिन बाद नियुक्त हुए ब्लॉक अध्यक्ष

दैनिक इंदौर संकेत

भोपाल • मप्र कांग्रेस ने आखिरकार 1100 में से 780 ब्लॉक के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। कल देर रात मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी की। 780 में करीब 325 उप-ब्लॉक भी शामिल हैं। कांग्रेस यह सूची पहले संगठन सृजन के तहत पचमढ़ी में हुए प्रशिक्षण वर्ग से पहले जारी करने वाली थी, लेकिन विवाद से बचने के लिए इसे रोक लिया।

अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के 122 दिन बाद जाकर यह सूची जारी की गई। लेकिन देरी से आई इस सूची में औसत आयु 50 वर्ष से नीचे रखी गई। लगभग 60 फीसदी से अधिक ब्लॉक अध्यक्ष 35 से 45 आयु वर्ग के हैं। करीब 80 फीसदी ब्लॉक अध्यक्ष नए बनाए गए हैं। जिन 20 फीसदी को रिपीट किया है, उनमें भी युवा वर्ग के अधिक हैं। कांग्रेस ने इस सूची के जरिए युवा वर्ग को ब्लॉक स्तर पर नेतृत्व देने की पहल की है। मप्र में कांग्रेस के अभी 71 संगठनात्मक जिले और 1100 संगठनात्मक ब्लॉक व उप ब्लॉक अध्यक्ष के पद हैं।

जिला कार्यकारिणी होगी छोटी, 3 फार्मेट तय किए

कांग्रेस संगठन ब्लॉक अध्यक्ष के बाद अब जिलों में कार्यकारिणी बनाने पर काम करेगा। लेकिन इस बार कार्यकारिणी छोटी रखी जाएगी। इसके लिए इस बार तीन फार्मेट तय किए हैं। पहला उन जिलों के लिए जिनमें 1 से 2 विधानसभा हैं में 50 से 55 पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

न्यूज ब्रीफ

शासकीय सेवकों के गुमशुदा जीपीएफ कटौत्रों के संबंध में विशेष शिविर प्रारंभ

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर द्वारा शासकीय सेवकों के जीपीएफ गुमशुदा कटौत्रे, निष्क्रिय जीपीएफ खाते, पार्ट वांट/फुल वांट एवं अप्रविष्ट मदों के प्रकरणों के निराकरण किये लिये कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 112 में विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रथम दिवस 15 दिसम्बर,2025 को शिविर में 14 विभागों के लगभग 85 कर्मचारियों के जीपीएफ प्रकरण प्राप्त हुये हैं। सभी विभागों से अपील की गयी है कि शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर अपने पेंडिंग प्रकरणों का निराकरण करवाएं। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में एवं वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्रीमती मोनिका कटारे के निर्देशन में सामान्य भविष्य निधि के गुमशुदा कटौत्रों तथा सामान्य भविष्य निधि जागरुकता से संबंधित शिविर का आयोजन 19 दिसम्बर 2025 किया जायेगा। इंदौर संभाग के सभी विभागों के कर्मचारियों की सूची जिनके गुमशुदा कटौत्रे हैं वह महालेखाकार ग्वालियर से आए दल द्वारा जिला कोषालय,इंदौर के माध्यम से व्हाट्सअप पर साफ्टकापी में प्रेषित कर दी गयी है।

गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा 7 मात्र शक्तियों को इंदिरा गांधी अवॉर्ड से सम्मानित किया

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा आयोजित विजय दिवस पर 7 मातृ शक्तियों को उनके द्वारा सामाजिक अन्य क्षेत्रों के गए उत्कर्ष कार्यों के लिए इंदिरा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कोरी समाज के वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती प्रेमलता धीमान को इन्दिरा अवार्ड से सम्मानित किया गया पंचायत संयोजक कैलाश चौधरी प्रकाश महावर पत्रकार ओमप्रकाश धीमान हीरालाल वर्मा समाजसेवी एवं गणेश वर्मा भारत आर्य नवीन चौधरी नरेश वर्मा दयाराम सोमेश महेन्द्र चिरगया आदि समाज वरिष्ट जन उपस्थित थे ।

सांवेर के इंडस्ट्रीज एरिया में तीन कन्फेंक्शनरी यूनिट में प्रदूषण बोर्ड ने की कार्रवाई

बिना ट्रीट किए गंदा पानी छोड़ रहे थे, व्यर्थ भूजल निकला जा रहा था

अनियमितताएं मिलने पर जारी किए गए नोटिस

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● शहर से लगे हुए सांवेर रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार को मप्र प्रदूषण बोर्ड (एमपीपीसीबी) ने छापामार कार्रवाई करते हुए तीन कन्फेक्शनरी यूनिट्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। यहां बिना ट्रीट किए फैक्ट्री का गंदा पानी छोड़ा जा रहा था, तो वहीं मनमाने तरीके से बिना अनुमति के भू-जल स्तर का उपयोग किया जा रहा था।

एमपीपीसीबी, इंदौर के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान, एमबी फूड प्राइवेट लिमिटेड, नॉटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, और आर.जे. कन्फेक्शनरी में गंभीर कमियां पाई गई, जिसके बाद बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए। सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर-ए में स्थित एमबी फूड प्राइवेट लिमिटेड में जांच में एमपीपीसीबी के अधिकारियों ने पाया कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहा था। यूनिट में ट्रीट किए गए गंदे पानी को मापने के लिए कोई फ्लो मीटर नहीं लगा था और भूजल निकालने के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से कोई अनुमति नहीं दिखा पाई। इंडस्ट्री भूजल की निकाली जा रही मात्रा का विवरण नहीं दे पाई। खतरनाक कचरे के भंडारण और निपटान से संबंधित रिकॉर्ड भी गायब थे, और साफ-सफाई की स्थिति खराब पाई गई। यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया कि ट्रीट किया गया गंदा पानी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जा रहा था। नॉटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में भी इसी तरह के

उल्लंघन पाए गए, जहां निरीक्षण के दौरान ईटीपी और फ्लो मीटर दोनों बंद पाए गए। ईटीपी संचालन से संबंधित लॉगबुक ठीक से नहीं रखी गई थी। यूनिट बिना फ्लो मीटर लगाए और बिना सीजीडब्ल्यूए की मंजूरी के बोरवेल से भूजल निकाल रही थी। खतरनाक कचरे के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, और मुख्य गेट पर खतरनाक कचरे की जानकारी देने वाला कोई अपडेटेड डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिला। यूनिट ट्रीट किए गए गंदे पानी को सीईटीपी में भेजे जाने का कोई सबूत भी पेश नहीं कर पाई। आरजे में और भी गंभीर उल्लंघन पाए गए। सेक्टर-बी में स्थित कन्फेक्शनरी, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जरूरी मंजूरी के बिना चल रही थी। इसका फ्लो मीटर काम नहीं कर रहे थे, और बिना इजाजत बोरवेल से ग्राउंडवॉटर निकाला जा रहा था। अधिकारियों को खतरनाक कचरे का गलत स्टोरेज, खराब हाउसकीपिंग, और ईटीपी से निकलने वाला कीचड़ छोटे कंटेनरों में बिना साईंटिफिक तरीके से रखा हुआ मिला। यह यूनिट प्लास्टिक कचरे और दूसरे इंडस्ट्रियल कचरे के बनने, स्टोरेज और निपटान के बारे में कोई जानकारी या रिकॉर्ड देने में भी नाकाम रही।

इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी

एमपीपीसीबी के रीजनल ऑफिसर सतीश चोकसे ने कहा कि तीनों यूनिट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें अपना जवाब देने और उल्बंधनों को ठीक करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। अगर इंडस्ट्रीज तय समय में नियमों का पालन नहीं करती हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम में सुधार नहीं करती हैं या जरूरी जानकारी जमा नहीं करती है, तो सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें बिजली और पानी की सप्लाई काटने की सिफारिशें भी शामिल हो सकती हैं. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे अचानक निरीक्षण जारी रहेंगे, और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ड्रग्स मुक्त मध्यप्रदेश एवं सड़क सुरक्षा अभियान का भव्य शुभारंभ

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● विगत दिन प्रेस्टीज कॉलेज में ड्रग्स मुक्त मध्यप्रदेश एवं सड़क सुरक्षा को लेकर मालवा टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित 'यूथ फॉर चेंज' अभियान का भव्य शुभारंभ बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर युवाओं को जागरूक करने हेतु रॉक बैंड द्वारा प्रभावशाली प्रस्तुति दी गई।

कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री अदा शर्मा ने महिला ढोल समूह के साथ ढोल बजाकर उत्साहपूर्वक नृत्य किया और अपनी प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थित युवाओं में ऊर्जा एवं सकारात्मक संदेश का संचार किया। इसके पश्चात एक वीडियो रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो

विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नशामुक्ति, सड़क सुरक्षा एवं सामाजिक जागरूकता से जुड़ी शॉर्ट फिल्मों एवं संदेशों का प्रसारण करेगा। अदा शर्मा ने युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें ड्रग्स से दूर रहने, सुरक्षित जीवनशैली अपनाने तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत युवाओं से होती है। इस अवसर पर मालवा टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले निर्माता राजेंद्र राठौर द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म 'जस्ट वन्स' का प्रीमियर अतिथियों एवं युवाओं के बीच किया गया, जिसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। फिल्म दिखा गया कि छोटे शहरों के बच्चे जब मेट्रो शहरों में आते हैं चकाचौंध नाइटलाइफ को दोस्तों के कहने पर ड्रग्स पीना शुरू कर देते हैं किस तरह से ड्रग्स की लत में पड़ जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं।

भारोत्तोलन में सुरेन्द्र पटेल को मिला प्रथम स्थान

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मप्र पश्चिम क्षेत्र की मेजबानी में 47 वीं अंतर क्षेत्रीय वेटलिफ्टिंग और बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता दिनांक 11 से 13 दिसम्बर तक आयोजित की गई, जिसमें 59 किलो केटेगरी में मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ तथा मप्र विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के पदाधिकारी ने 396 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पटेल ने अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में पहली बार शामिल होकर उपलब्धि हासिल की इससे प्रभावित होकर कंपनी के प्रबंध निदेशक महोदय ने इमेजिंग प्लेयर के खिताब से नवाजते हुवे विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया। ऐसे होनहार और प्रतिभावान खिलाडी का मप्र विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन इन्दौर व्दारा एक गरिमामय कार्य क्रम में अभिनंदन किया और उनको पुष्पमाला, स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आत्मानुरागी सम्मान किया।

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय 63वाँ स्थापना-दिवस समारोह मनाया

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्र. 1, इंदौर में केंद्रीय विद्यालय संगठन का 63 वाँ स्थापना-दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों एवं विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान सुधीर बाजपेई जी के द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। स्काउट व एनसीसी कैडेट्स ने अतिथियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया । सभी अतिथियों का हरित पादप भेंट कर स्वागत किया गया। उपप्राचार्या श्रीमती निरंजना सक्सेना ने स्वागत कथन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने केंद्रीय विद्यालय गीत प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिनमें केंद्रीय विद्यालय संगठन की उपलब्धियाँ व भारतीय संस्कृति की छटा निहित थी। सभी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन यात्रा प्रदर्शनी, मध्यभारत हिंदी साहित्यकारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

बिना सूचना दिए खड़ी फसल प्रशासन द्वारा नष्ट करने पर कलेक्टर कार्यलय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● ग्राम किशनपुरा तहसील देपालपुर के पारधी समाज को सन 1942 में होलकर शासन द्वारा दी गई भूमि पर काबिज फसल बिना सूचना दिए खड़ी फसल प्रशासन द्वारा नष्ट की गई पुन: स्थापित करने की मांग को लेकर जिला राजीव विकास केंद्र एवं मध्य प्रदेश पारधी समाज युवा समिति द्वारा कलेक्टर कार्यलय का घेराव कर कलेक्टर के नाम एडीएम को दिया ज्ञापन। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव इंदौर जिला राजीव विकास केंद्र झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दीपू पवार एवं भूपेंद्र केतके दिलीप ठक्कर के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय का इंदौर जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ राजीव विकास केंद्र एवं मध्य प्रदेश पारधी समाज युवा समिति सोसाइटी द्वारा घेराव कर कलेक्टर शिव वर्मा के नाम एक ज्ञापन एसडीएम श्रअजय भूषण शुक्ला को दिया गया। ज्ञापन कहां गया कि पारधी समाज के कई परिवार को होलकर रियासत ने सन 1942 में अपनी जीविका चलाने के लिए ग्राम किशनपुरा पंचायत बजरंग पुरा बेटमा तहसील देपालपुर जिला इंदौर में भूमि आवंटित की थी इसके माध्यम से पारधी समाज के लोगों कृषि कार्य कर खेती कर अपने परिवार की जीविका चला रहे थें किन्तु बेटमा थाना प्रभारी तहसील एवं तहसील दार द्वारा समाज के लोगों को बिना सुचना दिए ही समाज के लोगों की खड़ी फसल गेहूं चना सड़क के नाम पर नष्ट कर दी गई खेतों पर बने शेड भी तोड़ दिए हैं।

प्रत्येक नागरिक को आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का किया जा रहा है विस्तार-शुक्ल

दैनिक इंदौर संकेत

भोपाल ● राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और इसी उद्देश्य के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विगत 2 वर्षों में ऐतिहासिक और सर्वांगीण प्रगति की है। यह बात उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने जनसंपर्क संचालनालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। शासकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 से बढ़कर 19 हो चुकी है तथा निजी मेडिकल कॉलेज 12 से बढ़कर 14 हो गए हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र से दमोह, बुधनी और छतरपुर में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ सेवाएं भी सुदृढ़ होंगी। राजगढ़, मंडला और उज्जैन में मेडिकल कॉलेज स्थापना का कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें कटनी, धार, पन्ना और बैतूल में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, इंदौर में 50 एमबीबीएस सीटों के साथ शैक्षणिक गतिविधियां आरंभ हो चुकी हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि शासकीय एमबीबीएस सीटों की संख्या 2275 से बढ़कर 2850 हो गई है तथा शासकीय एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर कुल एमबीबीएस सीटें 5550 तक पहुंच चुकी हैं। पीजी (एमडी/एमएस) सीटों की संख्या 1262 से बढ़कर 1468 हुई है और कुल पीजी सीटें 2862 हो गई हैं। इसके साथ ही 93 सुपर स्पेशियलिटी सीटों की उपलब्धता से प्रदेश में उन्नत चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ सेवाओं को नया आयाम मिला है। अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर में अस्पताल भवन, मिनी ऑडिटोरियम, नर्सिंग हॉस्टल सहित विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 773.07 करोड़ रुपये, श्यामशाह मेडिकल कॉलेज, रीवा हेतु 321.94 करोड़ रुपये तथा सतना मेडिकल कॉलेज से संबद्ध नए अस्पताल के लिए 383.22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 13 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए 192.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रदेश भी देगा अनुकंपा नियुक्ति

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश न केवल हितग्राहियों बल्कि अपनें कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।1 अप्रैल से लागू हुए एच आर मैनुअल में कई कर्मचारी हितैषी नीतियाँ शामिल की गई थी जिनमें कर्मचारियों को प्रतिवर्ष संविदा अनुबंध के नवीनीकरण की आवश्यकता समाप्त दी गई थी। इसके अतिरिक्त कन्जूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार वार्षिक वेतनवद्धि का प्रावधान किया गया था। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिले के अंतर्गत स्नानतंरण का प्रावधान भी लागू किया गया था।

मिशन द्वारा जारी संविदा नीति में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी भी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना शामिल है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश अंतर्गत विभिन्न संवर्गों में 32,000 से अधिक संविदा कर्मचारी कार्यरत है तथा कई कर्मचारियों के साथ आकस्मिक मृत्यु जैसी दुखद: घटना पूर्व में देखी गई है।

इसे दृष्टिगत रखते हुए मिशन द्वारा किसी भी कर्मचारी-अधिकारी की आकस्मिक मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान जोड़ा गया है। पूर्व में आकस्मिक मृत्यु पर पीड़ित परिवार को केवल अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान था किंतु अब सेवारत मिशन कर्मचारी की मृत्यु होने पर पीडित परिवार का एक आश्रित सदस्य अनुकंपा नियुक्ति अथवा अनुग्रह राशि में से किसी का भी चुनाव कर पात्र होनें पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकता है।आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान के लिए सक्षम अधिकारी मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को नामांकित किया गया है।

मोहन सरकार का बड़ा फैसला : अब किसान की जमीन होगी सुरक्षित

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़ी लैंड पूलिंग योजना आखिरकार रद्द कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित इस योजना को किसानों के भारी विरोध और भारतीय किसान संघ के दबाव के बाद वापस लेना पड़ा। सीएम मोहन यादव ने इसे पूरी तरह निरस्त करने का आदेश जारी किया है। इस एक्ट में सरकार सिंहस्थ 2028 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थायी ढांचे बनाना चाहती थी। इसके तहत किसानों से जमीन लेकर उन्हें बदले में विकसित प्लॉट और बाजार दर पर मुआवजा देने का प्रस्ताव था। किसानों का कहना था कि योजना को स्वैच्छिक बताया गया, लेकिन व्यवहार में दबाव बनाया जा रहा था। यह भी स्पष्ट नहीं था कि विकसित भूमि कब मिलेगी, कितनी मिलेगी और मुआवजा किस आधार पर तय होगा।

आजीविका पर खतरे की आशंका

किसानों को डर था कि जमीन चली गई तो खेती और रोजगार दोनों पर असर पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में यही जमीन उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है।

भारतीय किसान संघ का बड़ा आंदोलन

योजना के विरोध में भारतीय किसान संघ ने 'घेरा डालो, डेरा डालो' आंदोलन का ऐलान किया। इसके बाद उज्जैन और आसपास के इलाकों में विरोध तेज होता चला गया।

पहले संशोधन, फिर विवाद

किसानों के विरोध के बीच सरकार ने पहले योजना में संशोधन का आदेश जारी किया, लेकिन संशोधन से भी किसानों की आशंकाएं दूर नहीं हुईं, उल्टा नाराजगी और बढ़ गई। 17 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान संगठनों से मुलाकात के बाद योजना निरस्त करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद संशोधन आदेश सामने आने से मामला दोबारा गर्मा गया।

भाजपा के भीतर भी मतभेद

भाजपा विधायक अनिल जैन समेत कई जनप्रतिनिधियों ने खुलकर किसानों का समर्थन किया। सरकार के भीतर बढ़ते मतभेदों ने भी फैसला बदलने में अहम भूमिका निभाई।

अंततः सरकार का फाइनल फैसला

लगातार विरोध, आंदोलन और राजनीतिक दबाव के बाद सरकार ने उज्जैन लैंड पुलिंग एक्ट खत्म को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब इस योजना पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी।

किसानों को बड़ी राहत

योजना रद्द होने से उज्जैन और आसपास के किसानों में खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन और आजीविका दोनों सुरक्षित रह गई हैं।

क्या कहा जारी आदेश में?

सरकारी आदेश में साफ किया गया है कि उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए प्रस्तावित लैंड पूलिंग योजना को किसानों के हित में निरस्त किया जाता है और इस पर आगे कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी।

उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में सरकार को बड़ा कदम पीछे लेना पड़ा है। यह फैसला दिखाता है कि संगठित किसान आंदोलन और जनदबाव सरकार की नीतियों को बदलने की ताकत रखते हैं।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
इंदौर, बुधवार 17 दिसंबर 2025

न्यूज ब्रीफ

जीण माता को सवा लाख सितारों से सजी 111 मीटर की चुनरी चढ़ेगी

इंदौर ●श्री जीणमाता सेवार्थ समिति द्वारा राजीव गांधी चौराहा स्थित शुभकारज गार्डन एबी रोड पर जीणमाता महोत्सव 21 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें जीणमाता का शक्ति मंगल पाठ, गजरा, चुनरी उत्सव होगा। महोत्सव में जीणमाता को सवा लाख सितारों से सजी 111 मीटर की चुनरी चढ़ेगी,फूल बंगला सजेगा। मंगल पाठ व 51 दीपों से महाआरती भी होगी। माता को 111 फीट गजरा भी चढ़ेगा।

समाजसेवी विनीता सुरेंद्र पाठक का आकस्मिक निधन

इंदौर ●साईं भक्त युवा समाजसेवी सुश्री विनीता- सुरेंद्र पाठक का आकस्मिक निधन हो गया है । वें एडव्होकेट स्व.सुरेंद्र पाठक और श्रीमती संगीता पाठक की पुत्री तथा केंद्रीय साईं सेवा समिति के अध्यक्ष गौतम पाठक की बड़ी बहन थी । युवा समाजसेवी सुश्री विनीता पाठक ने इंदौर में समाजसेवा व धार्मिक कार्यो के नए आयाम स्थापित किये जिसमें कोरोना में मृत लोगो लावारिस अस्थियों का विसर्जन, पार्थिव शिवलिंग पूजन, गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, निशुल्क शिर्डी यात्राएँ , गाय की रोटी हेतु वाहन, हर गुरुवार प्रसाद वितरण, निशुल्क प्याऊ और पानी के टैंकर, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, सकोरे व पौधों का वितरण, कन्या पूजन, रुद्राक्ष वितरण, कुश्ती प्रतियोगिता, विभिन्न रैलियों और यात्राओं का स्वागत मंच, साईं प्रभातफेरी व पालकी यात्रा में सक्रिय भूमिका जैसे अनेक उल्लेखनीय कार्य किये है ।

जनता के बीच रहे राधेश्याम पटेल, कांग्रेस को दे रहे नई मजबूती

देपालपुर ●देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधेश्याम पटेल अपनी सक्रियता, सादगी और जनसेवा के कारण तेजी से जनता के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं। वे लगातार गांव-गांव पहुंचकर आम लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं और हर छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रमों में सहभागिता निभा रहे हैं। राधेश्याम पटेल की मजबूत ज़मीनी पकड़ इसका प्रमाण है कि क्षेत्र का हर वर्ग उनसे जुड़ाव महसूस करता है। वे आमजन से बेहद सरलता और आत्मीयता से मिलते हैं, जिससे जनता में उनके प्रति विश्वास और सम्मान लगातार बढ़ रहा है। छोटे से बड़े, हर व्यक्ति तक उनकी पहचान और स्वीकार्यता है। उनकी यह सक्रिय कार्यशैली न केवल जनता के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि इससे कांग्रेस संगठन भी जमीनी स्तर पर सशक्त हो रहा है। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और संगठनात्मक मजबूती दिखाई दे रही है।

कोली समाज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 20 को कर्नाटक में

इंदौर ● देश के 17 करोड़ कोली/कोरी समुदाय का नेतृत्व करने वाले सर्वमान्य राष्ट्रीय संगठन अखिल भारतीय कोली समाज (रजि.) नईदिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर्नाटक प्रदेश के बैंगलोर में 20 दिसम्बर 2025 को कर्नाटक इलेक्ट्रिक सीटी बोर्ड (चश्वक्ष) इंजिनियर्स एसोसिएशन आडोटोरियम आनंदराव सर्कल बैंगलोर में निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता में होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने इन्दौर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पत्रकार प्रकाश महावर कोली इन्दौर से कार से भोपाल जाएंगे, वहां से यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन से बैंगलोर के लिए रवाना होंगे। कोली समाज की इस बैठक में पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गये सदस्यता अभियान, नशामुक्त भारत अभियान एवं एक पैड़ मां के नाम अभियान की समीक्षा के साथ ही देश भर के विभिन्न उपसमूह एवं विभिन्न नामों से जाने-पहचाने जाने वाले कोली समाज तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के एकीकरण को लेकर विस्तृत चर्चा होगी।

विधानसभा सत्र के दिन धारा 163 लागू, 5 किमी दायरे में पांच से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध

भोपाल (एजेंसी) ● प्रदेश की 16वीं विधानसभा के सत्र को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बुधवार 17 दिसंबर को आहूत विधानसभा सत्र के दौरान लोकशांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त भोपाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 17 दिसंबर को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक अथवा सत्रावसान तक (जो पहले हो) प्रभावी रहेगा। पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार विधानसभा भवन के आसपास और चिन्हित मार्गों पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली, आम सभा, पुतला दहन या आंदोलन की अनुमति नहीं होगी।

हथियार और भारी वाहनों पर सख्ती

आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू, धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर जैसे भारी वाहनों तथा यातायात बाधित करने वाले तांगा, बैलगाड़ी आदि के आवागमन पर भी रोक रहेगी।

व्यवधान फैलाने पर कार्रवाई

शिक्षण संस्थानों, होटलों, दुकानों, उद्योगों और निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों-अधिकारियों, विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।

इन क्षेत्रों में रहेगा आदेश प्रभावी

निषेधाज्ञा लिली टॉकीज से 7 बटालियन मार्ग, रोशनपुरा, बाणगंगा चौराहा, राजभवन-ओल्ड विधानसभा मार्ग, जिंसी-शब्बन-पुरानी जेल मार्ग, स्लॉटर हाउस रोड, बोर्ड ऑफिस चौराहा, ठंडी सड़क, 74 बंगला, रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक रोड, दूरदर्शन रोड, भारत भवन रोड से मुख्यमंत्री निवास तक, नवीन विधानसभा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, पत्रकार भवन, विधायक विश्राम गृह, सतपुड़ा, विंध्याचल, वल्लभ भवन, अरेरा एक्सचेंज सहित आसपास के संवेदनशील इलाकों में प्रभावी रहेगा।

भोजपुरिया वेलफेयर सोसाइटी का छठ मिलन समारोह संतोष सभागृह पर संपन्न होगा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ●भोजपुरिया वेलफेयर सोसाइटी का छठ मिलन समारोह 21 दिसंबर रविवार के दिन संतोष सभागृह पर होगा भोजपुरिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बंटेश्वर नाथ सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भोजपुरिया समाज छठ मिलन समारोह का आयोजन करने जा रहा है जिसमें कई कार्यक्रम व समाज के वरिष्ठ नागरिक व पदाधिकारी का सम्मान किया जाएगा कार्यक्रम के पश्चात भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया गया है कार्यक्रम में मुख्य रूप से भोजपुरिया समाज के विनोद पंडित, मनोज शर्मा, जयप्रकाश सिंह, महेंद्र जैन, शैलेश सिंह, नंदलाल सिंह, हेमंत कुंवर सिक्वार, अरविंद सिंह, रामकिशोर पाल आदि समाज के लोग उपस्थित होंगे

शहरों क्षेत्र में सुधरेंगी सड़कें और बनेंगे सामुदायिक भवन

भोपाल (एजेंसी) ● देवास के कारकम की रोड चौड़ी की जा रही है। यह रोड पिछले चार साल से जर्जर थी। इस सड़क से हर दिन करीब 50 हजार वाहन निकलते हैं। इसके चौड़ीकरण और निर्माण के साथ स्ट्रीट लाइन के काम में पांच करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। देवास में ही नहीं बल्कि प्रदेश के नगरीय निकायों में सड़कों के निर्माण, पुल पुलिया, कम्युनिटी हॉल, पाथवे सहित अन्य विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक दिए गए हैं। निकायों की मांग और जरूरतों के अनुसार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जबलपुर सहित अन्य निकायों को करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं। यह काम निकायों को एक साल के अंदर पूरा करना होगा। इसमें विकास कार्यों के लिए कई निकायों ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। विधायकों को भी पांच करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे शहरी क्षेत्रों में विधायक आम जनता की मांग के अनुसार विकास कार्य करा सकेंगे। यह काम नगरीय निकायों के माध्यम से होना है, विधायकों के सहमति होना जरूरी है। विधायकों के यहां से प्रस्ताव तैयार होकर कलेक्टर के यहां से निकायों में भेजे गए हैं। यह राशि विधायक अपने क्षेत्र में ही विकास कार्यों के लिए ही खर्च कर सकेंगे। इस निधि के माध्यम से सौंदर्गीकरण का काम नहीं कराया जा सकेगा। निकाय चुनाव वर्ष 2027 में प्रस्तावित है। इसमें जनप्रतिनिधियों के सामने सड़क, बिजली पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों को लेकर वोट मांगने जाना है। ऐसी स्थिति में स्थानीय लोगों की मांग अनुसार प्रस्ताव दिए गए हैं।

अमृत योजना को भी एक वर्ष में पूर्ण करने के लिए निकायों और निर्माण एजेंसियों को कहा गया है। अमृत योजना एक के तहत भोपाल, इंदौर जबलपुर, रीवा, कटनी सहित 35 शहरों में सीवेज और पानी का काम पिछले आठ वर्ष से चल रहा है, जो अब अंतिम चरण में है। अमृत - 2 में हर घर तक पानी पहुंचाने का काम और सीवेज का काम किया जा रहा है, जिसे दो वर्ष के अंदर पूरा करने के लिए कहा गया है। निकायों में चुनावी वर्ष तक यह काम करीब 60 फीसदी पूरा हो जाएगा, इससे 80 फीसदी शहरवासियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास कल्याण बोर्ड के सदस्य पाटनी आएंगे 18 को

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ●विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य भरत भाई पाटनी मध्य प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर 18 दिसंबर की शाम को इन्दौर आएंगे। तीन दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर 18 दिसंबर शाम को इन्दौर आएंगे। ये जानकारी देते हुए डीएनडी डेवलपमेंट के प्रदेश अध्यक्ष श्याम नायक एवं बंजारा जन - विकास सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश मानावत ने बताया कि भारत सरकार के सदस्य विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास कल्याण बोर्ड के भरत भाई पाटनी तीन दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर 18 को शाम इन्दौर आएंगे एवं 19 दिसंबर को इन्दौर कलेक्टर कार्यालय पर प्रात: 11 बजे आएंगे। आप विमुक्त घुमंतू जनजाति समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे । उसके पश्चात 4 करोड़ 30 लाख रुपए करीब सैंज यूनिवर्सिटी के पास म्यूजिक संग्रहालय के निर्माण कार्य का अवलोकन करेंगे फिर विमुक्त घुमंतू जनजाति छात्रावास सांवेर के दो छात्रावास का अवलोकन कर बच्चों से मिलेंगे । विमुक्त घुमंतू जनजाति के अति पिछड़ी बस्तियों में रहवासीयो से मिलकर समस्या जानेंगे उसके पश्चात रात को अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उ ज्जैन के लिए रवाना होंगे। 20,21 को उज्जैन में अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम के सामाजिक सम्मेलन में शामिल होंगे ।

सरकार दो साल का ढिंढ़ोरा पीट रही, किसानों को खाद, बीज और उपज का दाम तक नहीं मिल रहा - सचिन यादव

भोपाल (एजेंसी) ● प्रदेश में मोहन सरकार के दो साल पूरे होने पर एक तरफ जहां मंत्रीगण अपने-अपने विभागों की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी सरकार की खामियां बताने में लगी है। पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद से कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सचिन यादव ने कहा- 2 साल का सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मध्यप्रदेश में किसानों का हाल बेहाल है। सरकार की नीतियों के कारण किसानों की स्थिति खराब है। कमलनाथ सरकार ने 1 साल में किसानों के लिए काम किया।

सचिन यादव ने कहा हमारी नीतियों में सबसे ऊपर किसान थे। 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण हमारी सरकार ने दिया। हमारी सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ। बीजेपी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे बिजली नहीं, अघोषित कटौती हो रही है। 2025 में सोयाबीन की सरकारी खरीदी बंद हो गई भावांतर जैसी लूट की योजना चालू कर दी गई। इससे किसानों में नाराजगी है। सचिन यादव ने कहा- भाजपा ने वादा किया था कि किसानों को निरंतर 10 घंटे बिजली देंगे। सोयाबीन की खरीद पर नियमित सरकारी खरीदी और उसे और मजबूत करना। गेहूं ?2700/क्विंटल, धान ?3100/क्विंटल का वादा भी झूठा निकला।

सचिन यादव ने कहा- गेहूं-धान के घोषित भाव और खरीदी की गारंटी दोनों

नदारद हैं। भाजपा ने वादा किया था सोयाबीन की खरीद पर नियमित सरकारी खरीदी और उसे और मजबूत करना है। किसानों को फसल का भाव नहीं मिला रहा। प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिलता। खाद मांगने पर किसानों पिटाई की जाती है। गुणवत्ताहीन खाद बांटी जाती है इसमें मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। गलत तरीके से प्रदेश में खाद बांटी जा रही है इसमें एमपी दूसरे नंबर पर है। ये आंकड़े कांग्रेस के नहीं लोकसभा में दिए गए आंकड़े हैं। सचिन यादव ने कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा- कमलनाथ सरकार ने किसान को राहत नहीं, संरक्षण की गारंटी दी थी। जय किसान ऋण मुक्ति योजना में ?2 लाख तक फसल ऋण माफ किया। 10 ।क्तक बिजली बिल आधा किया। मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना से प्याज किसानों को सही दाम दिलाने का प्रयास किया था।

हजारों समाजबंधुओं ने मनाया प्रभु पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक-पालनाजी में झूले भगवान

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● एयरपोर्ट रोड स्थित महावीर बाग पर नवरत्न परिवार एवं शहर के श्वेताम्बर जैन समाज की भागीदारी में पहली बार रविवार को पार्श्व जन्म कल्याणक में पालना भक्ति महोत्सव के साथ ही भगवान के दस भावों की झांकी एवं भक्ति संगीत का दिव्य आयोजन किया गया। शहर के प्रमुख जिनालयों में स्थापित मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिकृतियों को पालनाजी में विराजित कर भगवान को झुलाने का गरिमापूर्ण उत्सव शहर के जैन बंधुओं ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाया। दादा पार्श्वनाथ के जयघोष के बीच कड़ाके की शीत लहर के बावजूद 2 हजार से अधिक समाजबंधुओं ने अपने आराध्य भगवान पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव को मनोहारी साज-सज्जा एवं भक्ति संगीत के बीच अनूठे अंदाज में आत्मसात किया। आयोजन समिति के प्रमुख संयोजक ललित सी. जैन, मनीष सुराणा एवं प्रीतेश ओस्तवाल ने बताया कि महोत्सव में शहर के सभी प्रमुख जिनालयों में मूल नायक के रूप में स्थापित पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिकृति को पालनाजी में विराजित कर भगवान का झूला झुलाने के लिए शहर के गणमान्य जैन बंधुओं में होड़ सी लगी रही। पहली

बार प्रभु के दस भावों की मनोहारी झांकी भी श्रृंगारित की गई और मालवांचल के भक्ति संगीत से जुड़े कलाकारों सुश्री अदिति कोठारी, खैरागढ़ के संभव लुनिया, मंदसौर के आशीष मराठा, इंदौर की मोक्षा सुराणा ने अपनी भक्ति रचनाओं की प्रस्तुतियों से हजारों समाजबंधुओं को 5.7 डिग्री तापमान में भी बांधे रखा। सूत्रधार थे मोहनखेड़ा के देवेश जैन और मंच का संचालन किया सचिन जैन ने। हितेंद्र मेहता, विमल घोड़ावत, संजय नाहर, जीनेश्वर जैन, राजेंद्र जैन,महेंद्र सुराना अजीत ललवानीसहित बड़ी संख्या में शहर के जैन संगठनों के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

7वीं मंजिल से छात्र ने कूदने की कोशिश की, कल्याण मार्ट की बिल्डिंग की बालकनी पर खड़ा था

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● राजेन्द्र नगर स्थित कल्याण मार्ट में एक छात्र ने मंगलवार देर शाम 7वें माले से छलांग लगाने की कोशिश की। सूचना के बाद पुलिस और फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची। राजेन्द्र नगर पुलिस की सूझबूझ से युवक को बचाया गया। बताया जा रहा है कि वह कर्ज से परेशान है। टीआई नीरज बिरथरे ने बताया कि रेती मंडी चौराहे पर स्थित कल्याण मार्ट में मंगलवार शाम एक छात्र गोकुल, पुत्र विक्रम पाटीदार, निवासी गोपुर पहुंचा था। वह मार्ट में घूमते हुए 7वें माले तक पहुंच गया और वहां की बालकनी से छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। उसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही टीआई सहित थाने का बल मौके पर पहुंचा और काफी समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। टीआई के अनुसार, गोकुल लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और मूल रूप से रतलाम का रहने वाला है।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बधाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश नि:शुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

कार्यालय का पता
5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर,
गुरुद्वारे के सामने, इंदौर
संपर्क: 94250-64357, 94245-83000

सम्पादकीय

हाईवे पर हो रही मौतों के लिए क्या सिर्फ ड्राइवर जिम्मेदार? कोर्ट ने सरकार और एनएचएआइ से पूछा - जवाबदेह कौन

पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर जिस तरह के हादसे हुए, उसमें वाहन चालकों की लापरवाही या चूक को जिम्मेदार बताया जा सकता है। मगर सड़क किनारे बने ढाबे या होटल भी इसका बड़ा कारण बन रहे हैं, क्योंकि अक्सर इनके सामने ट्रक या अन्य वाहन खड़े कर दिए जाते हैं और वहां से गुजरने वाली कोई अन्य गाड़ी उनसे टकरा जाती है। ऐसे अनेक मामले सामने आए, जिसमें पिछले महीने की शुरुआत में राजस्थान के फलोदी में एक टेम्पो ट्रेवलर के सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकराने की घटना ने सबका ध्यान खींचा था। उसमें दस महिलाओं और चार बच्चों सहित पंद्रह लोगों की जान चली गई थी। इस घटना का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और ऐसे हादसों को लेकर चिंता जताई थी। उसी मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआइ और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताई। अदालत ने यह भी कहा कि एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बने अवैध ढाबे तथा होटल सड़क हादसों की बड़ी वजह बन रहे हैं और इसे रोकने के लिए पूरे देश में लागू होने वाले दिशा-निर्देशों पर विचार किया जाएगा। यह कोई छिपी बात नहीं है कि लंबी दूरी की निर्बाध सड़कों के किनारे कई जगहों पर ढाबे या होटल तो बना दिए जाते हैं, लेकिन वहां सड़क से अलग हट कर वाहन लगाने के लिए जगह नहीं होती। नतीजतन, वहां खाने-पीने आदि के लिए रुकने वाले लोग अपनी गाड़ी सड़क किनारे ही खड़ी कर देते हैं। जबकि ऐसी सड़कों पर आमतौर पर वाहनों की रफ्तार काफी तेज होती है और पीछे से आने वाली गाड़ियों के टकराने की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर सड़क किनारे बिना रोकटोक के ऐसे ढाबे और होटल चलने की जिम्मेदारी किसकी है? एक ही प्रकृति के लगातार हादसों और ज्यादातर घटनाओं में कारण स्पष्ट होने के बावजूद सरकार की ओर से अब तक इस दिशा में कोई पहल क्यों नहीं की गई? इसी को रेखांकित करते हुए अदालत ने सवाल उठाया है कि इस तरह के ढाबों पर कार्रवाई के लिए कौन-से नियम हैं और अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। हैरानी की बात है कि लगातार सड़क हादसों के कारणों की पहचान करके उसे दूर करने के लिए सरकार और संबंधित महकमों को खुद अपनी ओर से जो पहल करनी चाहिए थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को ध्यान दिलाना पड़ता है। देश भर में अच्छी सड़कों का जाल तो बिछाया जा रहा है, लेकिन उन पर सफर भी उतनी ही सुरक्षित हो, यह सुनिश्चित करने का सवाल एक तरह से हाशिये पर छोड़ दिया गया है।

कैंसर बीमारी-भारत की चुनौतियाँ और नीति सुधार की अनिवार्यता

आधुनिक जीवनशैली, पर्यावरणीय प्रदूषण, तंबाकू, शराब का बढ़ता सेवन,तनाव और शारीरिक निष्क्रियता से कैंसर अब केवल वृद्धावस्था तक सीमित नहीं रही,कार्यशील आयु वर्ग को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रही- वैश्विक स्तर पर कैंसर आज केवल एक चिकित्सकीय बीमारी नहीं रह गया है,बल्कि यह वैश्विक स्तरपर मानवसभ्यता के लिए एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक औरनीतिगत चुनौती बन चुका है। दुनियाँ के लगभग हर देश में कैंसर मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल है और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसे नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज के सबसे खतरनाक रूपों में गिनती हैं। कैंसर की भयावहता इस तथ्य से समझी जा सकती है कि यह मानवीय शरीर पर विभिन्न स्वरूपों में हमला करता है कभी फेफड़ों के रूप में, कभी स्तन, सर्वाइकल, प्रोस्टेट, लिवर या रक्त कैंसर के रूप में,और कई बार तब तक पहचान में नहीं आता जब तक यह जीवन के लिए गंभीर खतरा यानें स्टेज फोर या अंतिम समय न बन जाए। आधुनिक जीवनशैली, पर्यावरणीय प्रदूषण, खानपान में बदलाव, तंबाकू और शराब का बढ़ता सेवन, तनाव और शारीरिक निष्क्रियता ने कैंसर को एक ऐसी बीमारी बना दिया है जो अब केवल वृद्धावस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि कार्यशील आयु वर्ग को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। वैश्विक रिपोर्टों और स्वास्थ्य अध्ययनों के अनुसार, 40 से 50 वर्ष की आयु के लोगों में कैंसर के मामलों में आने वाले वर्षों में तीव्र वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। 2030 तक यह आयु वर्ग कैंसर के सबसे बड़े जोखिम समूहों में शामिल हो सकता है।यह स्थिति इसलिए और भी चिंताजनक है क्योंकि यही वर्ग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और पारिवारिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यदि इस आयु वर्ग में बड़ी संख्या में लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, तो इसका प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्पादकता, रोजगार गरीबी, सामाजिक असमानता और मानसिक स्वास्थ्य तक गहराई से महसूस किया जाएगा।यही कारण है कि आज कैंसर से मुकाबला केवल अस्पतालों और डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं रह गया है, बल्कि यह सार्वजनिक नीति,शासन व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन की मांग करता है। साथियों बात अगर हम कैंसर से प्रतिरक्षात्मक उपायों की करें तो जीवनशैली परिवर्तन, कैंसर रोकथाम की पहली सीढ़ी है,कैंसर के बढ़ते मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल इलाज पर आधारित रणनीति पर्याप्त नहीं है। रोकथाम,समय पर जांच और प्रारंभिक निदान ही इस बीमारी से लड़ने के सबसे प्रभावी हथियार हैं। जीवनशैली में बदलाव जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम,तंबाकू और शराब से दूरी, मानसिक तनाव को नियंत्रित करना और प्रदूषण से बचाव,कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। विकसित देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं निवारक उपायों पर केंद्रित है। स्कूल स्तर से लेकर कार्यस्थलों तक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ताकि लोग बीमारी के शुरुआती संकेतों को समझ सकें और समय रहते जांच करा सकें। भारत जैसे

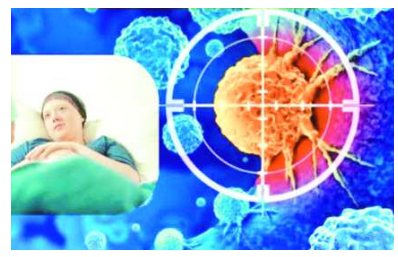

विकासशील देश में, जहां स्वास्थ्य संसाधनों पर पहले से ही भारी दबाव है, जीवनशैली आधारित रोकथाम और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। साथियों बात अगर हम भारत में कैंसर: बढ़ता संकट और असमानताएँ इसको समझने की करें तो,भारत में कैंसर की स्थिति वैश्विक रुझानों से अलग नहीं है,बल्कि कई मामलों में यह और अधिक गंभीर है। जनसंख्या का विशाल आकार, सामाजिक- आर्थिक असमानताएँ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं का अंतर, और जागरूकता की कमी,ये सभी कारक कैंसर के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां निजी अस्पताल और उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कई बार बुनियादी संसाधनों से वंचित रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ग्रामीण मरीजों में कैंसर का पता अक्सर बहुत देर से चलता है, जब इलाज की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। इस असमानता का सीधा असर मृत्यु दर पर पड़ता है और यही कारण है कि भारत में कैंसर से होने वाली मौतों का अनुपात कई विकसित देशों की तुलना में अधिक है। बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेपकारी भूमिका, एक ऐतिहासिक मोड़ इसको समझने की करें तो,भारत में कैंसर प्रबंधन की खामियों को उजागर करने में न्यायपालिका की भूमिका हाल के वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा कैंसर को देशव्यापी अधिसूचित बीमारी घोषित करने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह याचिका एम्स के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ डॉ. अनुराग श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई, जिसमें देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में कैंसर प्रबंधन से जुड़ी गंभीर कमियों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया। 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को औपचारिक नोटिस जारी किया जाना यह दर्शाता है कि अब इस मुद्दे को केवल नीति-स्तर की चर्चा तक सीमित नहीं रखा जा सकता।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को केवल एक कानूनी प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में देखा है। अदालत ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि यदि सरकारें समय रहते ठोस कदम नहीं उठातीं, तो इसका खामियाजा लाखों नागरिकों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। न्यायपालिका का यह रुख भारत में स्वास्थ्य अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। कैंसर को अधिसूचित बीमारी का दर्जा क्यों है यह इतना जरूरी? इसको समझने की करें की करें तो किसी बीमारी को अधिसूचित घोषित करने का अर्थ यह होता है कि उसके मामलों की रिपोर्टिंग कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाती है।अस्पतालों प्रयोगशालाओं और डॉक्टरों को ऐसे मामलों की जानकारी सरकार को देनी होती है,जिससे बीमारी के प्रसार,भौगोलिक वितरण और जोखिम कारकों का सटीक आकलन किया जा सके।भारत में टीबी, मलेरिया, कोविड-19 जैसी कई बीमारियां अधिसूचित हैं, जिसके कारण इनके मामलों पर निगरानी और नियंत्रण अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से किया जा सका। कैंसर को अभी तक देशव्यापी स्तर पर अधिसूचित न किया जाना एक गंभीर नीतिगत चूक मानी जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 17 ने ही अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों के तहत कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। इसका अर्थ यह है कि देश का लगभग आधा हिस्सा अभी भी कैंसर मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग से बाहर है।जब बीमारी के वास्तविक आंकड़े ही सरकार के पास नहीं होंगे, तो प्रभावी नीति निर्माण कैसे संभव हो पाएगा? यही वह बुनियादी प्रश्न है जिसने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया। साथियों बात अगर हम आईसीएमआर कैंसर रजिस्ट्री: सीमित कवरेज,सीमित समझ इसको समझने की करें तो, भारत में कैंसर के आंकड़ों का मुख्य स्रोत इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा संचालित कैंसर रजिस्ट्री है। लेकिन याचिका के अनुसार, यह रजिस्ट्री फिलहाल देश की केवल लगभग 10 प्रतिशत आबादी को ही कवर करती है। ग्रामीण इलाकों में यह कवरेज मात्र 1 प्रतिशत के आसपास है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश में कैंसर के वास्तविक मामलों का एक बड़ा हिस्सा कभी आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज ही नहीं हो पाता।जब डेटा अधूरा होगा,तो उस पर आधारित रणनीतियां भी अधूरी और अप्रभावी ही होंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कई देशों में कैंसर रजिस्ट्री की कवरेज 80 से 100 प्रतिशत तक है। इन देशों में कैंसर की रोकथाम, स्क्रीनिंग और इलाज की योजनाएं इसी व्यापक डेटा के आधार पर बनाई जाती हैं। भारत में डेटा की यह कमी न केवल नीति निर्माण को कमजोर करती है, बल्कि शोध और नवाचार की संभावनाओं को भी सीमित कर देती है। नई दवाओं, उपचार पद्धतियों और रोकथाम कार्यक्रमों के विकास के लिए सटीक और व्यापक आंकड़े अनिवार्य होते हैं। साथियों बात अगर हम ग्रामीण भारत और कैंसर एक अदृश्य संकट इसको समझने की करें तो,ग्रामीण भारत में कैंसर की स्थिति को अक्सर अदृश्य संकट कहा जाता है। जागरूकता की कमी,सामाजिक रूढ़ियां,आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव ये सभी कारक मिलकर कैंसर को एक मूक हत्यारा बना देते हैं। कई बार मरीज शुरुआती लक्षणों को सामान्य बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक वे किसी बड़े अस्पताल तक पहुंचते हैं,तब तक बीमारी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी होती है। अधिसूचित बीमारी का दर्जा मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंसर मामलों की पहचान और रिपोर्टिंग बेहतर हो सकती है, जिससे समय पर हस्तक्षेप संभव होगा। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय अनुभव: भारत के लिए सबक इसको समझने की करें तो,अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने कैंसर को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के रूप में देखा है। यूरोप,उत्तरी अमेरिका और कुछ एशियाई देशों में कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों को सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। नियमित मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, कोलोनोस्कोपी और लो-डोज सीटी स्कैन जैसे परीक्षणों को उच्च जोखिम समूहों के लिए अनिवार्य या अत्यधिकप्रोत्साहित किया गया है। इन देशों में कैंसर को अधिसूचित बीमारी के रूप में देखने का लाभ यह हुआ कि नीति निर्माण डेटा-आधारित और लक्ष्य-उन्मुख बन सका। भारत यदि इन अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीख लेकर कैंसर को देशव्यापी अधिसूचित बीमारी घोषित करता है, तो यह न केवल आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली की जवाबदेही भी बढ़ाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा और संसाधनों का आवंटन वास्तविक जरूरतों के अनुसार किया जा सकेगा। हम नीति सुधार और भविष्य की दिशा इसको समझने की करें तो,कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करना केवल पहला कदम होगा। इसके साथ-साथ व्यापक नीति सुधारों की भी आवश्यकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर स्क्रीनिंग सुविधाओं का विस्तार, जिला स्तर पर कैंसर उपचार केंद्रों की स्थापना, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स का एकीकृत ढांचा ये सभी कदम समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कैंसर उपचार को पर्याप्त कवरेज देना और मरीजों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर जवाब तलब करना यह संकेत देता है कि अब कैंसर को नजरअंदाज करने की गुंजाइश नहीं बची है।यह मामला केवल कानूनी बहस का विषय नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन और भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि समय रहते ठोस कदम उठाए गए, तो भारत न केवल कैंसर से होने वाली मौतों को कम कर सकता है, बल्कि एक मजबूत, डेटा-आधारित और न्यायसंगत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की ओर भी बढ़ सकता है। अत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि एक साझा जिम्मेदारी, अंतत: कैंसर से लड़ाई सरकार, न्यायपालिका चिकित्सा समुदाय और समाज,सभी की साझा जिम्मेदारी है। जीवनशैली में बदलाव से लेकर नीति सुधार तक, हर स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की पहल ने इस बहस को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है।अब यह सरकारों पर निर्भर करता है कि वे इस अवसर को एक ऐतिहासिक सुधार में बदलती हैं या इसे भी एक और फाइल में बंद कर देती हैं। कैंसर जैसी भयावह बीमारी के संदर्भ में देरी का अर्थ है अनगिनत जिंदगियों का नुकसान। इसलिए समय की मांग है कि भारत कैंसर को देशव्यापी अधिसूचित बीमारी घोषित कर, एक मजबूत और संवेदनशील सार्वजनिक स्वास्थ्य भविष्य की नींव रखे। -संकलनकर्ता लेखक-**किशन सनमुखदास भावनानी,** गोंदिया

आंचलिक

सिंचाई करते किसान की हार्ट अटैक से मौत रात में बिजली सप्लाई के कारण खेत गए थे

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन ● कसरावद क्षेत्र में मंगलवार को एक किसान की खेत में सिंचाई करते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। छोटी कसरावद निवासी 52 वर्षीय सुरेंद्र सिंह चौहान रात में अपनी फसल को पानी देने गए थे, तभी कड़ाके की ठंड में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। परिजनों के अनुसार, सुरेंद्र सिंह रात करीब 1 बजे खेत पर गए थे। सुबह जब वे घर नहीं लौटे, तो परिवार के सदस्य उनकी तलाश में खेत पहुंचे। वहां सुरेंद्र सिंह बेसुध हालत में पड़े मिले। उन्हें तत्काल कसरावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन लखन सिंह चौहान ने बताया कि सुरेंद्र सिंह रात भर खेत में सिंचाई कर रहे थे। सुबह काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने खेत में जाकर देखा, तब इस घटना का पता चला। इस घटना से क्षेत्र के किसानों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर गहरा रोष है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में कुल 10 घंटे में से 4 घंटे बिजली की आपूर्ति रात के समय अलग-अलग शिफ्टों में की जा रही है। 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच रात में सिंचाई करने में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन और बिजली कंपनी के स्तर पर इस व्यवस्था का विरोध भी जताया है। शीतलहर के बीच रात में जान जोखिम में डालकर खेतों में सिंचाई करना उनकी मजबूरी बन गई है।

किसान ने मुफ्त बांटे 200 क्विंटल तरबूज, लाल नहीं निकले तो व्यापारी ढाई रुपए किलो में मांग रहे थे

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन ● एक किसान की मेहनत पर पानी फिर गया। यहां टांडा बरूड गांव के एक किसान ने अपनी ढाई एकड़ की तरबूज की खड़ी फसल लोगों को मुफ्त में बांट दी। वजह थी- तरबूज का अंदर से लाल न निकलना और बाजार में बेहद कम दाम मिलना। खेत से ही लोग थैले भर-भरकर 200 क्विंटल से ज्यादा तरबूज ले गए। टांडा बरूड गांव के किसान रामेश्वर कुमरावत ने देवली गांव स्थित अपने खेत में तरबूज लगाए थे। फसल अच्छी थी और फल 3 से 4 किलो तक के हो गए थे। लेकिन जब इन्हें काटा गया, तो इनमें अपेक्षित सुर्ख लाल रंग नहीं निकला। खरगोन, बमनाला, राजपुर और कसरावद से आए व्यापारियों ने जब माल देखा, तो रंग फीका होने के कारण उन्होंने मात्र ढाई रुपए प्रति किलो का थोक भाव लगाया। किसान के मुताबिक, इस फसल में करीब 80 हजार रुपए की लागत आई थी और उन्हें 3 से 4 लाख रुपए

कमाई की उम्मीद थी। व्यापारियों द्वारा लगाए गए दाम से सिंचाई और मेहनत का खर्च भी नहीं निकल पा रहा था। इससे निराश होकर रामेश्वर ने पूरी फसल मुफ्त बांटने का फैसला किया। परिजनों ने बताया कि जब दाम नहीं मिल रहे, तो इसे 'धर्म का काम' मानकर लोगों को बांट दिया गया।

कुआं बंद करने पर विवाद, खेत मालिक पर पानी में यूरिया डालने का आरोप

दैनिक इंदौर संकेत

बुरहानपुर ● जिले के ग्राम डोंगरगांव में मंगलवार को 50 साल पुराने कुएं को बंद किए जाने की कोशिश के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। कुआं बंद करने पहुंचे खेत मालिक की जेसीबी पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान एक कार को भी नुकसान पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। गांव के निवासी और अधिवक्ता शेर सिंह पवार ने बताया कि यह कुआं पिछले 40 से 50 वर्षों से ग्रामीणों के उपयोग में है। सरकारी रिकॉर्ड में भी यह कुआं 'निस्तार' के रूप में दर्ज है, यानी इसका उपयोग सार्वजनिक तौर पर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने आठ दिन पहले ही थाने में शिकायत भी की थी। ग्रामीण बसंती बाई ने बताया कि पिछले आठ दिनों से गांव में पानी की भारी परेशानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुएं में तीन बोरी यूरिया डाल दी गई, जिससे पानी खराब हो गया।

कांग्रेस ने विजय शाह का पुतला जलाया रोकने आए अफसरों पर चलाई वाटर कैनन

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● रतलाम में बतौर प्रभारी मंत्री विजय शाह के लाड़ली बहना को लेकर दिए गए बयान ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार को उनके गृह जिले खंडवा में महिला कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। शहर के बीच चौराहे पर मंत्री का पुतला फूंका गया। इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस और प्रशासनिक अमले से भी झड़प हो गई। कांग्रेस ने कहा कि मंत्री दादागिरी कर रहे हैं, वहीं प्रशासन उनकी चापलूसी में लगा हुआ हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन के दौरान एक अनोखा वाकया देखने को मिला। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ने प्रदर्शन रोकने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेसियों के बीच पहुंचे शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी को चेतावनी देने लगे कि यहां से हट जाओ। रघुवंशी ने कहा कि, हम लोग हमारी जगह पर खड़े है, हमारा काम कर रहे है, आप दूर जाकर आपकी ड्यूटी कीजिए। इस पर बजरंग बहादुर ने कहा कि मैं सिटी मजिस्ट्रेट हूं, इस पर रघुवंशी ने कहा- मजिस्ट्रेट हो तो मैं क्या करूं। प्रतिभा रघुवंशी के जवाब से बजरंग बहादुर चिढ़ गए। उन्होंने फायर ब्रिगेड (वाटर कैनन) के कर्मचारी से कहा कि इन पर पानी डालो, रघुवंशी ने फिर कहा कि पानी डालकर दिखाओ। इतने में एक कर्मचारी वाटर कैनन का पाइप लेकर पहुंच गया। उसे कांग्रेस नेता शहजाद पंवार ने रोकने की कोशिश की। फिर छीनाझटकी होने लगी, इसी बीच प्रतिभा रघुवंशी ने खुद पाइप थाम लिया और सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सहित कोतवाली थाना प्रभारी को गीला कर दिया। खुद को भीगते देखकर अधिकारी दूर चले गए।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि, दुख का विषय है कि मंत्री विजय शाह हमारे जिले से आते हैं। वे लगातार महिलाओ का अपमान कर रहे है। पहले सेना के शौर्य का अपमान किया और अब खुले रूप से दादागिरी बताने लगे हैं। रतलाम में बताने तो गए थे सरकार की दो साल की उपलब्धियां लेकिन डराने और धमकाने का काम करने लगे। जब वोट चाहिए था तो उन्हें लाडली बहना दिख रही थी। वहीं लाड़ली बहना प्रदेश में बढ़ते हुए अत्याचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, उनके बच्चों की बेरोजगारी के खिलाफ आज सरकार से जवाब तलब करने लगी है तो आप उसे डरा रहे हैं।

मंत्री विजय शाह कह रहे हैं कि, जिन महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, वो हमारे राजनीतिक कार्यक्रम में हमारे नेताओं का सम्मान करने नहीं पहुंची तो उनके खिलाफ जांच कराएंगे। इन्हें तो शर्म आना चाहिए। सत्ता में बैठे है, इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद की जमीन-जायजाद बेचकर पैसा दे रहे हैं। ये जनता का पैसा है, जो टैक्स के रूप में जनता देती है। यह महिलाओं का वैधानिक अधिकार हैं। केवलराम चौराहे पर हुए पुतला दहन के दौरान कांग्रेसियों ने गांधी भवन से रैली निकाली। चौराहे पर पहुंचने के बाद नारेबाजी की और पुतला दहन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष उत्तपालसिंह पुरनी, रचना तिवारी, हेमलता पालीवाल, मुमताज बी, कामिनी मंडलोई, मीनू मंडलोई, रूपा कास्डे, नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर, प्रेमांशु जैन, विशाल जैन, मनोज मंडलोई, हुकुम मेलुंदे आदि मौजूद थे।

ओंकारेश्वर में नर्मदा में पलटी नाव, रैलिंग में इंजन का पंखा फंसा, संतुलन बिगड़ा

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● र तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में सोमवार शाम नर्मदा नदी में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां ब्रह्मपुरी घाट के पास श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई। नाव में 11 लोग सवार थे, जो नदी में गिर गए। गनीमत रही कि सभी ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे वे डूबने से बच गए और उनकी जान बच गई।

हादसा तब हुआ जब नाव ब्रह्मपुरी घाट से मंदिर की ओर मुड़ रही थी। इसी दौरान नाव के इंजन का पंखा पानी के नीचे पत्थर और रेलिंग से टकराकर फंस गया। इससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। नाव में सवार महिलाओं और बच्चों समेत सभी श्रद्धालु पानी में गिर गए।

मांधाता पुलिस ने बताया कि श्रद्धालु अमरावती, रायपुर, गोरखपुर और सूरत से आए थे। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद अन्य नाविकों ने फुर्ती दिखाई और महज 5 मिनट के भीतर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि डैम के गेट खुले होने के कारण नदी का बहाव तेज था। साथ ही, नाव में क्षमता से अधिक सवारियां होने की भी आशंका जताई जा रही है।

आज लखनऊ में सीरीज जीतने उतरेगा भारत

इकाना में बराबरी पर रहेगी साउथ अफ्रीका की नजर, शाम सात बजे से मुकाबला

लखनऊ (एजेंसी) • भारतीय टीम जब बुधवार को यहां एकाना स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी-20 मुकाबले में जीत की मुहर लगाने के इरादे से मैदान में उतरना चाहेगी, लेकिन कुछ खिलाडियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भी दर्शकों की निगाहें टिकी होंगी। पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर चुकी मेज बान टीम आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी, खासकर पिछले मैच की जीत के बाद। धर्मशाला टी-20 में एक बार फिर साबित हुआ कि अभिषेक शर्मा भारत की विस्फोटक शुरुआत के लिए कितने अहम हैं। अभिषेक के जोड़ीदार शुभमन गिल ने जहां 28 गेंदों पर 28 रन बनाए। गिल के अलावा भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी पिच पर संघर्ष करते नजर आए। गेंदबाजी की बात करें, तो अक्षर पटेल के चले जाने से पश्चिम बंगाल के ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को अपना लोहा मनवाने का मौका मिला है। वह इस मौके को दोनों हाथों से लपकना चाहेंगे। इस बीच, दक्षिण अफ्रीका खुद के हालात ढाक के तीन पात की तरह हैं। तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में उनकी चिर परिचित खामियां सामने आईं। पिच पर गेंद की हरकत और भारतीय गेंदबाजों के अनुशासन के सामने केवल एडन मार्करम ही पिच पर टिके रहे। अगर मेहमान टीम को सीरीज को जिन्दा रखना है तो मार्करम और ड्वेक्वटन डी कॉक को अब मजबूती के साथ पारी की शुरुआत देनी होगी। ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर पर भी यह जिम्मेदारी होगी कि फिरकी गेंदबाजों के आने के बाद पारी की रफ्तार धीमी न पड़े। प्रोटियाज के पास एनरिच नाट्र्जे, लुंगी एनगिडी और मार्को यानसेन जैसे गेंदबाज़ मौजूद हैं, जो अपनी रफ्तार से किसी भी बल्लेबाज़ी क्रम को ढेर कर सकते हैं।

बुमराह निजी कारणों से घर लौटे, अंतिम टी20 में हो सकती है वापसी

मुंबई (एजेंसी) •भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने कहा है कि टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से अपने घर वापसी चले गये हैं। इस कारण उन्हें टीम से बाहर रखा गया है। इससे पहले बुमराह के अचानक ही टीम से बाहर होने के कारण कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे। बीसीसीआई और टीम प्रबंधन के अनुसार परिवार में मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए ही बुमराह को घर लौटना पड़ा है। गौरतलब है कि बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में भी शामिल नहीं थे। इसी कारण उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में जगह मिली थी। एक रिपोर्ट में बीसीसीसीआई के हवाले से कहा गया है कि बुमराह के परिवार का एक सदस्य गंभीर रुप से बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती है। इसी कारण उन्हें घर लौटना पड़ा है। उनके चौथे या पांचवें टी20 में वापसी की उम्मीदें हैं। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बुमराह अहमदाबाद में होने वाले पांचवें टी20 मुकाबले के लिए टीम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी उनकी , प्राथमिकता अपने परिवार के साथ रहना और स्थिति संभालना है।

आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे बिके कैमरुन ग्रीन

अबू धाबी (एजेंसी) • इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19 वें सत्र के लिए हुई नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरुन ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। ग्रीन को कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने मिनी नीलामी में 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। 369 खिलाड़ी इस नीलामी में उतरें। इसमें 77 स्लॉट के लिए बोली लगी। ग्रीन ने बससे अधिक कीमत को लेकर अपने ही देश के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। स्टार्क को साल 2024 में हुई नीलामी में केकेआर ने ही 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। पहले सेट में 6 खिलाड़ी नीलामी पूल में लाए गए पर इनमें से केवल 2 ही बिके। दिल्ली कैपिटल्स ने डेविड मिलर को 2 करोड़ रुपए में अपने साथ शामिल किया। वहीं जेक फ्रेजर-मैकगर्क, डेवोन कॉन्वे, सरफराज खान और पृथ्वी शॉ नहीं बिके। इन पर किसी भी टीम ने ने बोली नहीं लगाई। ग्रीन के लिए शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में काफी टक्कर हुई पर बोली 11 करोड़ से ऊपर बोली पहुंचते ही राजस्थान पीछे हट गयी। इसके बाद चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) आगे आई। इसके बाद केकेआर और सीएसके के बीच ग्रीन को पाने होड़ रही। सीएसके ने आईपीएल इतिहास में कभी किसी खिलाड़ी पर इतनी ज्यादा राशि की बोली नहीं लगाई थी। जितनी 24 करोड़ की बोली ग्रीन पर लगायी लेकिन केकेआर ने 25.2 करोड़ रुपये में बाजी मार ली

मां हमेशा हौसला देती थी: पारुल

मुंबई (एजेंसी) • फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज होने पर पारुल गुलाटी ने अपनी खुशी जाहिर की। अभिनेत्री का कहना है कि यह फिल्म उनके लिए खास है। उनकी पहली फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने 15 साल के लंबे सफर की कहानी सुनाई। पारुल ने बताया कि उनकी मां हमेशा हौसला देती थी और कहती थीं कि तेरी किस्मत का कोई नहीं छीन सकता। अगर ऊपर वाले की मेहर होगी, तो तुझे वो भी मिल जाएगा, जो तेरी नहीं है। पारुल ने अपने सफर को याद करते हुए कहा, मैंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी। उसके बाद वेब सीरीज की, पंजाबी फिल्में भी की, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं चली। फिर मैंने जाकर बिजनेस शुरू किया। कई बार लगा शायद एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, लेकिन इस बीच मुझे कभी एक्टिंग छोड़ने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि एक्टिंग मेरे लिए एक शादी की तरह है और बिजनेस मेरा बच्चा है। अभिनेत्री ने बताया कि जब-जब उन्हें रिजेक्शन मिलते थे, तो उनके मन में सवाल उठता था कि कहीं मेरे में तो कमी नहीं है। लेकिन, मां समझाती थीं, निशु, तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ लिखा है।

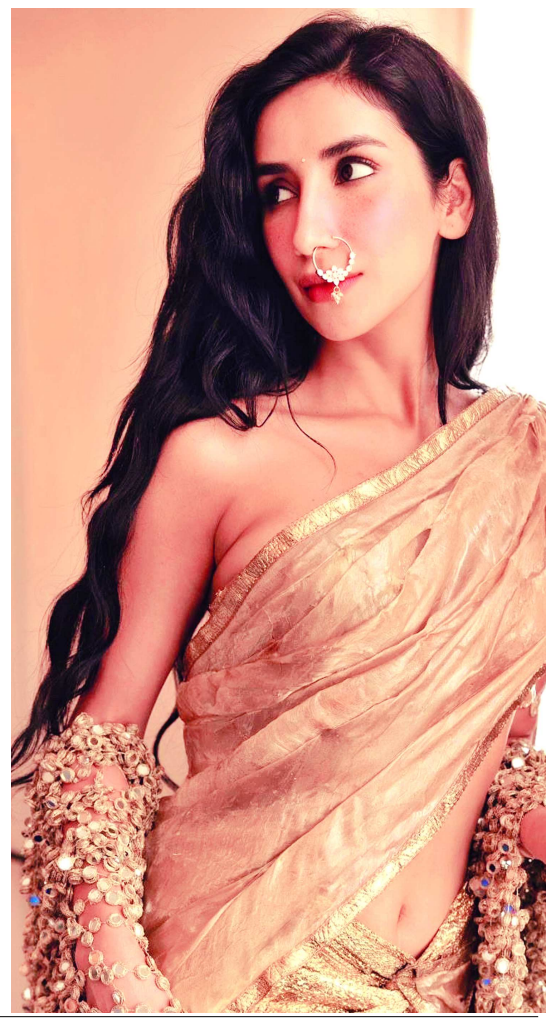

यूलिया ने अपनी मातृभाषा में रिलीज़ किया पहला गीत

मुंबई (एजेंसी) • कलाकार यूलिया वंतूर ने अपने करियर का एक बेहद भावनात्मक अध्याय शुरू किया है। यूलिया ने अपने गृह देश रोमानिया और अपनी मातृभाषा में पहला गीत रिलीज़ किया है, जिसका शीर्षक 'कोलिंदे, कोरिंदे' है। यूलिया के लिए यह गीत न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से खास है, बल्कि इसकी प्रस्तुति भी ऐतिहासिक रही। इस कैरल को पहली बार वेटिकन में पॉल षष्टम हॉल में प्रस्तुत किया गया, जहां पोप लियो चौदह की उपस्थिति में और दुनिया भर के प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं व हजारों लोगों के सामने नोस्त्रा एताते के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह में इसका प्रदर्शन हुआ। यूलिया वंतूर के लिए यह गीत किसी सपने के सच होने जैसा है। उनका कहना है कि वे वर्षों से रोमानियाई भाषा में गाना चाहती थीं, लेकिन उनका पहला रोमानियाई गीत एक क्रिसमस कैरल होना जैसे पहले से तय था।

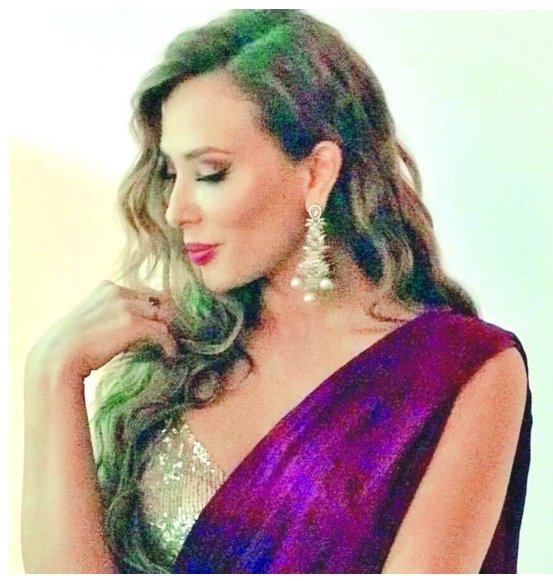

उज्जैन संभाग

नकली दवा बनाने, बेचने वालों को तीन साल की सजा, 6 लाख रुपए जुर्माना, 9 साल पहले खाद्य एवं औषधि विभाग ने मारा था छापा

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • कोर्ट ने 9 साल पुराने मामले में मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए नकली दवा बनाने वाले चार आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने सभी को 3 साल के कारावास और 6 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों में नकली दवा बनाने, रखने और बेचने वाले शामिल हैं। मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रसाधन, उज्जैन के संयुक्त जांच दल ने 21.09.2016 को सिमको आर्गेनिक्स के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच की थी। जांच दल में शामिल औषधि निरीक्षक लोकेश गुप्ता,

अल्केश यादव और अजय ठाकुर ने मेसर्स सिमको आर्गेनिक्स, नागझिरी, देवास रोड, उज्जैन पहुंचकर निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि आरोपी संतोष कुमार धींग के पास ऐलोपैथिक औषधि निर्माण का लाइसेंस नहीं था। तलाशी के दौरान उनके यहां पैकिंग में उपयोग की गई 2.6 किलोग्राम प्रिंटेड एल्यूमिनियम लेबल फाइल और पैकिंग मशीन बरामद हुई। इन दवाओं का निर्माण आरोपी राजेन्द्र शर्मा, मेसर्स सॉफ्ट मेडिकेप्स लिमिटेड, इंदौर के माध्यम से कराया जा रहा था। आरोपी प्रवीण शाह, मेसर्स अल्पा ऐलोपैथिकल लैबोरेटरी के द्वारा उक्त औषधियों की जांच रिपोर्ट अधिनियम के विपरीत फार्म 39 में जारी की गई थी। आरोपी शांतीलाल, मेसर्स शांतीलाल, बैंगलोर के माध्यम से ऐलोपैथिक औषधियों की बिक्री लगभग 24 लाख रुपए की गई थी।न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियोजन की साक्ष्य और अंतिम तर्कों के आधार पर आरोपीगण को दंडित किया। उज्जैन न्यायालय ने आरोपी संतोष कुमार धींग (उम्र 64 वर्ष, निवासी शिवाजी पार्क कॉलोनी, देवास रोड, उज्जैन), राजेन्द्र शर्मा (विजय नगर, जिला इंदौर), प्रवीण शाह (इंदौर) और शांतिलाल (बैंगलोर) को औषधि प्रसाधन अधिनियम की धाराओं 18(सी) और 27(बी)2 के तहत 3 साल के कारावास और 6 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में मार्गदर्शन प्रभारी उप-निदेशक (अभियोजन) राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर एवं पैरवी उमेश सिंह तोमर, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

मालवी पशु प्रजनन केंद्र में अव्यवस्था, कर्मचारी हड़ताल पर, पशुओं को नहीं मिल रहा आहार

दैनिक इंदौर संकेत

आगर - मालवा • मालवी नस्ल का एकमात्र पशु प्रजनन केंद्र इन दिनों गंभीर अव्यवस्थाओं और विवादों के कारण चर्चा में है। केंद्र के सभी 22 आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे पशु प्रजनन केंद्र की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। इसका सीधा असर केंद्र में मौजूद गोवंश और भैंसवंश पर पड़ रहा है। हड़ताल के कारण पशुओं के शेड की नियमित सफाई नहीं हो पा रही है, जिससे जगह-जगह गंदगी फैल गई है और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। पशुओं को पर्याप्त आहार भी नहीं मिल पा रहा है, जिसका उनकी सेहत पर प्रतिकूल असर हो रहा है। केंद्र में कई गोवंश लंपी वायरस से प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिनका समय पर इलाज नहीं हो पा रहा। मंगलवार को एक बीमार भैंस को तड़पते हुए देखा गया, जिससे पशु प्रेमियों में चिंता है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारी पंकज चौहान ने बताया कि पशुओं के इलाज के लिए आई कुछ दवाइयों को परिसर में बंद पड़े गोबर गैस प्लांट में फेंक दिया गया है, जिससे उनका उपयोग नहीं हो पा रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पशुओं को दिया जा रहा भूसा मिट्टी युक्त है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

कर्मचारियों के अनुसार, मृत पशुओं का विधिवत अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा रहा है। उन्हें केंद्र के पीछे जंगल में फेंक दिया जाता है, जहां वे कुत्तों और अन्य जानवरों का भोजन बन रहे हैं। वहीं, केंद्र प्रबंधक डॉ. राजीव खरे ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने दावा किया कि सभी व्यवस्थाएं सामान्य हैं और पशुओं की देखभाल में कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। प्रबंधन ने बताया कि हड़ताल के चलते वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कुछ मजदूर लगाए गए हैं, ताकि पशुओं की देखरेख जारी रह सके।

डॉ. खरे ने लंपी वायरस से पशुओं के ग्रसित होने की बात स्वीकार की है। उन्होंने पशुओं के अंतिम संस्कार में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात भी कही है।

महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, महाकाल व कॉरिडोर को बनाएंगे वूमन फ्रेंडली

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • महाकाल मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए अकेली आ रही हैं तो यह खबर आपके काम की है। मंदिर परिसर और कॉरिडोर को वूमन फ्रेंडली बनाया जाएगा। इसके लिए मंदिर की 1100 महिला कर्मचारियों को बारी-बारी से 15 दिन तक रोज एक घंटे ट्रेनिंग दी जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, मप्र पर्यटन बोर्ड, सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट 17 दिसंबर से इसकी शुरुआत करेंगे। पहली बैच में मंदिर की 38 कर्मचारियों को ट्रेनिंग से जोड़ा जाएगा। उप प्रशासक सिम्मी यादव को इसकी नोडल अफसर बनाया है। वे ट्रेनिंग के बाद महिला दर्शनार्थियों का फीडबैक भी लेंगी। मंदिर परिसर को महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड भोपाल की डॉ. रंजना मिश्रा ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में कार्यरत महिला कर्मचारियों को उज्जैन में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल के तहत महिला अनुकूल संवेदनशील कॉरिडोर बनाने पर ट्रेनिंग दी जाएगी।

इसमें उन्हें सिखाएंगे कि अकेली महिला के दर्शन-पूजन के लिए आने पर उन्हें किस प्रकार का सहयोग दें। ऐसी महिलाएं तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, उन्हें कैसे मदद की जा सके। बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें पैदल चलने में परेशानी आती है, उन्हें दर्शन के साथ प्रसाद लेने में भी गुड फील हो, इस तरह का वातावरण बनाया जाएगा।

खुद महसूस किया, महिलाओं से अच्छा व्यवहार नहीं होता

महिलाओं के लिए ट्रेनिंग का मसौदा लेकर आई मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड भोपाल की डॉ. रंजना मिश्रा ने कहा कि उन्होंने खुद महसूस किया कि परिसर में महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। वे जब प्रसाद लेने गई तो कई लोगों ने आवाज देकर बुलाया कि पांच रुपए में प्रसाद।

जब वे प्रसाद लेने आगे बढ़ी तो उन्हें कहा गया कि यह तो 80 रुपए की है। उन्होंने पूछा कि आप तो इसे पांच रुपए की बता रहे थे। जवाब मिला कि यहां तो इसी रेट में मिलेगा। पांच में मिले तो आप कहीं और से ले लीजिए। डॉ. मिश्रा ने कहा कि इसी व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। शुरुआत मंदिर की महिला कर्मचारियों से करेंगे। बाद में पुरुष कर्मचारियों को भी सिखाएंगे।

विक्रमादित्य विवि की कार्यपरिषद की बैठक आज एजेंडे में 35 से अधिक नियमित बिंदुओं के साथ महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक 17 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पूर्व में स्थगित 29 सितंबर की बैठक के 35 से अधिक नियमित बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष की अनुमति से कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा होगी।

यह बैठक पहले 29 सितंबर को निर्धारित थी, लेकिन सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह बैठक मुख्य प्रशासनिक भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में कुलगुरु प्रो. अर्पण भारद्वाज की अध्यक्षता में होगी। बैठक के एजेंडे में 35 से अधिक नियमित बिंदुओं के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें विश्वविद्यालय की उत्तरपुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन कराने का प्रस्ताव प्रमुख है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन फंड के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति भी कार्यपरिषद से ली जाएगी।

अन्य एजेंडा बिंदुओं में शिक्षकों के पेंशन प्रकरण, स्थायी कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करना, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के मामले, विश्वविद्यालय के नामकरण की सूचना, परीक्षा परिणाम तैयार करने वाली नई कंपनी

को कार्य देने के बाद कार्यपरिषद का अनुमोदन, पूर्व में हुई इंजीनियरिंग की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के रोके गए परिणामों पर चर्चा और अतिथि विद्वानों के विज्ञापन से संबंधित चर्चा शामिल है। इस बीच, विक्रम विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए साक्षात्कार शुरू हो गए हैं। विभिन्न अध्ययनशालाओं में कार्यरत प्राध्यापकों को लंबे समय बाद यह पदोन्नति दी जा रही है। लगभग 18 प्राध्यापकों के साक्षात्कार सोमवार से विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रारंभ हुए। मंगलवार को भी अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों ने शिक्षकों के साक्षात्कार लिए। सभी साक्षात्कार पूरे होने के बाद बंद लिफाफे कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाएंगे। बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद ही पदोन्नति के आदेश जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इन साक्षात्कारों के लिए विशेषज्ञों के नाम राजभवन द्वारा तय किए जाते हैं।

बच्ची से रेप की कोशिश, हत्या, पड़ोसी ने बोरी में भरकर मोगरी से पीटा

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन •उज्जैन के खाचरोद में रेप करने में नाकाम होने पर 9 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मासूम रविवार को नानी के घर आई थी। पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने पहले दुष्कर्म करने की कोशिश की। चिल्लाने पर उसने बच्ची को बोरी में बंद कर दिया। फिर मोगरी से लगातार वार किए। गंभीर हालत में बच्ची को रतलाम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। खाचरोद पुलिस ने बताया कि बच्ची रविवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण अपनी दो बड़ी बहनों के साथ नानी के घर आई थी। नानी और बड़ी बहनें रविवार दोपहर को छत पर बैठी थीं। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। काफी देर तक बच्ची घर नहीं आई तो नानी ने उसकी बहन को भेजा लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। पड़ोस में रहने वाला रियाज खान अपने घर के अंदर से बेहोश बच्ची को उठाकर लाया। बच्ची का मुंह सूजा था। सिर, नाक, आंख पर चोट लगी थी। खून निकल रहा था।

कलेक्टर शिवम वर्मा का आभार...

दिव्यांग संदीप सुमराह ने जनसुनवाई के माध्यम से अपनी संपत्ति का हक मिलने पर कलेक्टर के प्रति जताया आभार

पेंटाथॉलान खेल स्पर्धा में पदक जितने वाली भूमि अग्रवाल ने कलेक्टर वर्मा के प्रति जताया आभार

रात्रि चौपाल में गांव की समस्या हल होने पर सरपंच और ग्रामीणों ने कलेक्टर वर्मा का स्वागत कर जताया आभार

कलेक्टर वर्मा ने जनसुनवाई में दिव्यांग खिलाड़ियों को सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिये दी आर्थिक मदद

न्यूज ब्रीफ

7वें माले से कूदने वाला था लॉ स्टूडेंट, पुलिस ने बचाई जान

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित कल्याण मार्ट में मंगलवार देर शाम हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां एक छात्र ने इमारत की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि, मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक को सुरक्षित बचा लिया। बताया जा रहा है कि युवक कर्ज के कारण तनाव में था। रेती मंडी चौराहे पर स्थित कल्याण मार्ट में मंगलवार शाम गोकुल नाम का एक युवक पहुंचा। वह मार्ट में घूमते हुए सातवें माले तक चला गया। वहां पहुंचकर वह बालकनी से छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। इमारत के सिक्योरिटी गार्ड की नजर जब उस पर पड़ी, तो उसने बिना देर किए तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही राजेंद्र नगर टीआई नीरज बिरथरे अपने स्टाफ और फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंच गए। गोकुल मूल रूप से रतलाम का रहने वाला है और इंदौर में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता का नाम विक्रम पाटीदार है। बताया जा रहा है कि छात्र भारी कर्ज में डूबा हुआ है, जिसके चलते वह मानसिक रूप से काफी परेशान था और उसने यह आत्मघाती कदम उठाने का फैसला किया।

आईएएस संतोष वर्मा, न्यायाधीश के बीच मिलीभगत से हुआ आदेश

लेन-देन बिगड़ा तो हुई रिपोर्ट, पुलिस जांच इसी ओर जुटी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● आईएएस संतोष वर्मा के महिला अपराध संबंधी केस में बरी होने के कोर्ट आदेश की जांच चल रही है। वहीं, ब्राह्मणों पर विवादित बयान देने वाले बयान पर मध्यप्रदेश शासन ने वर्मा की बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। वहीं, केवल बयान बर्खास्तगी का आधार नहीं बनते हैं। ऐसे में वर्मा ने कोर्ट का आदेश मिलीभगत से बनवाया और इसमें अवैध कृत्य किया यह साबित करना जरूरी है। पुलिस महकमे की जांच अब इसी एंगल पर टिक गई है।

संतोष वर्मा यह दे रहे हैं सफाई

इस पूरे मामले में संतोष वर्मा मुख्य रूप से यह सफाई दे रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश किया था। इसकी उन्हें सत्यापित कॉपी मिली और यही डीपीसी में लगाई है। इसके आधार पर आईएएस अवार्ड हुआ। आदेश फर्जी हुआ या क्या हुआ इसमें उनका कोई लेना-देना नहीं।

इधर न्यायाधीश कह रहे हैं मैंने आदेश नहीं किया

उधर संतोष वर्मा के केस से बरी होने का आदेश 6 अक्टूबर 2020 को हुआ था। यह आदेश न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत की कोर्ट ने लिया था। इस पर रावत ने 27 जून 2021 में एमजी रोड थाने में अज्ञात के खिलाफ आवेदन कर खुद एफआईआर कराई थी। इसमें उन्होंने कहा कि वह 6 अक्टूबर को छुट्टी पर थे। यह आदेश उनकी कोर्ट से नहीं बना, यह फर्जी है। न्यायाधीश रावत ने कहा कि- लसूडिया थाने में संतोष वर्मा पर दर्ज एफआईआर क्रमांक 851/2016 (धारा 323, 294 व 506) का फौजदारी केस 1621/2019 चल रहा है।

यह केस अन्य कोर्ट से ट्रांसफर होकर मेरी (न्यायाधीश रावत) कोर्ट में 3 अक्टूबर 2020 को चढ़ाया गया था। सुनवाई के लिए 23 नवंबर 2020 लगाई गई थी। फिर इसमें साक्ष्य के लिए 22 फरवरी 2021 तारीख लगाई गई थी। फिर अगली तारीख 31 मई 2021 लगी थी। मेरी कोर्ट के जरिए 6 अक्टूबर 2020 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। मेरी पत्नी बीमार हैं, इसलिए इस दिन 6 अक्टूबर को मैं अवकाश पर था।

फिर 114 बार बात क्या इसलिए हुई

इस मामले में एक बात और आई है कि वर्मा और न्यायाधीश रावत के बीच में 114 बार मोबाइल पर बात हुई है। दोनों की कई बार मोबाइल लोकेशन एक जैसी रही यानी मुलाकात भी हुई है। इसके लिए पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि यह बातचीत कोर्ट आदेश यानी 6 अक्टूबर 2020 के बाद अधिक हुई है।

क्योंकि इस आदेश को लेकर दोनों के बीच में जो लेन-देन की डील थी वह बिगड़ गई थी। कोर्ट में बने आदेश के बाद यह लेन-देन पूरा नहीं हुआ था। इसके चलते दोनों के बीच कई बार फोन कॉल हुए थे और इस कमिटमेंट को पूरा किया जाए।

हालांकि इसके लिए कहा जा रहा है कि पत्नी की तबीयत (वर्मा और रावत दोनों की) खराब थी। बड़वानी में एक जगह इस रोग के उपचार को देख रहे थे, इसलिए यह बात हुई थी।

बीच में जिला अभियोजन अधिकारी की भूमिका

इस मामले में जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख की भूमिका भी संदिग्ध रही है। न्यायाधीश रावत ने आवेदन में बताया कि शेख ने मौखिक रूप से कहा था कि इस केस में समझौता हो गया है। इसकी स्कैन कॉपी भी है। इसमें भी इस निर्णय की तारीख 6 अक्टूबर लिखी हुई थी। सील मेरी कोर्ट की लगी थी और हस्ताक्षर अंग्रेजी में अपठनीय थे। वहीं, इस दिनांक को मेरे जरिए कोई आदेश नहीं किए गए था। यह फैसला कॉपी कूटरचित तैयार की गई है।

पुलिस ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि आदेश को भी चतुराई से कोर्ट में 6 अक्टूबर को सुबह 4 से 7 बजे के बीच किया गया था। फिर न्यायाधीश अवकाश पर रहे। इन्हीं बातों को जुटाने के लिए न्यायाधीश के मोबाइल को भी पुलिस ने मांगा है। यह अभी तक उन्हें नहीं मिला है।

हालांकि पुलिस ने कोर्ट से कई अहम फाइल और दस्तावेज, रिकॉर्ड जब्त किए हैं। फिलहाल न्यायाधीश रावत को जिला कोर्ट से इसमें अग्रिम जमानत मिल चुकी है।

परिवहन विभाग के अमले को चालानी कार्रवाई के लिए मिली पीओएस मशीनें

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● परिवहन विभाग ने प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत राज्य के परिवहन चेकपोस्टों को बंद कर दिया है। इनके स्थान पर 45 रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट जांच का कार्य कर रहे हैं। जांच के लिये प्रवर्तन बल, इंफोर्समेंट फोर्स को बॉडीवॉर्न कैमरे उपलब्ध कराये गये हैं। इन कैमरों की निगरानी में पीओएस मशीन के माध्यम से वाहनों के विरुद्ध ऑनलाइन चालानी कार्रवाई की जा रही है। राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा ई-चेकपोस्ट मॉडल के माध्यम से ऑनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा दी गई है। प्रवर्तन अमले द्वारा बॉडीवॉर्न कैमरे का उपयोग करने से वाहन चेकिंग के दौरान प्रत्येक कार्यवाही की मॉनीटरिंग वास्तविक समय, रियल टाइम में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से की जा रही है। जिससे वाहन जांच की व्यवस्था में पारदर्शिता आ रही है। अमले को पीओएस मशीन उपलब्ध कराने से वाहनों के विरुद्ध की जाने वाली चालानी कार्रवाई को ऑनलाइन तथा कैशलेस किया जा रहा है। प्रदेश में मोटरयान परिवहन से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन पर स्व-चलित पद्धति ई-डिटेक्शन को नवम्बर-2025 से लागू कर दिया गया।

प्रदेश में 45 रोड सेफ्टी एण्ड इन्फोर्समेंट के माध्यम पाँच

परिवहन की कई सेवाएं हुई फेसलेस

वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि से संबंधित सेवाओं को एनआईसी के पोर्टल वाहन तथा सारथी ऐप के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। इस व्यवस्था में आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सेवा प्राप्त कर पा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित फेसलेस सेवाओं की सूची में से प्रदेश में समस्त सेवाओं को फेसलेस रूप में प्रदान किया जा चुका है।

धार गुरुद्वारा कमेटी सचिव की सचिव की सलूजा ट्रैवल्स बस से गुजरात जा रही थी शराब, सचिव बोले इन्होंने रखवाई थी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ●इंदौर से अहमदाबाद जा रही सलूजा ट्रैवल्स की बस में शराब तस्करी पकड़ी गई है। बस से विजयनगर थाना पुलिस ने 7.50 लाख रुपए कीमत की विदेशी शराब पकड़ी है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इन पर आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले की पड़ताल करने पर यह बस धार गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सचिव अमित सिंह सलूजा की पाई गई है।

यह बस एमपी 09 एक्यू 1300 नंबर की है, जो मुस्कान अरोड़ा जयपुर निवासी के नाम पर है। इस बस का संचालन धार में सलूजा के जरिए किया जाता है, जो धार में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में पदाधिकारी हैं।

इन्होंने बताया कि इस बस का लंबे समय से वह संचालन कर रहे हैं। बस में माल गुजरात भेजने के लिए विशाल यादव ने भेजा था। यह बोलकर कि इसमें कीटनाशक है और अहमदाबाद जाना है। कीटनाशक के नाम से ही बिल और बिल्टी भी थे। यादव पहले भी शराब तस्करी में पकड़ा जा चुका है। हमें शराब की जानकारी नहीं थी। हाल ही में गुजरात की अवैध शराब लाइन को लेकर सख्ती की गई थी। इससे इंदौर से गुजरात लाइन लगभग ठप हो गई है। ऐसे में महंगे ठेके का ठेका लेकर घाटे में आए शराब ठेकेदार कमाई का रास्ता निकालने में जुटे हैं। इसके लिए अब बस से तस्करी का रास्ता निकाला गया है। अब पुलिस इस पकड़ी गई अवैध शराब के बैच से ठेकेदार को तलाश रही है। हालांकि, जानकारों के मुताबिक, एक ही बैच का माल कई ठेकेदारों के पास जाता है। ऐसे में यह जानकारी केवल पूछताछ में ही पता चल सकती है कि माल किसने भेजवाया था। हालांकि, प्रारंभिक तौर पर इसमें इंदौर के किसी बड़े शराब ठेकेदार का नाम सामने आ रहा है।

इस तरह पकड़ी गई थी शराब

विजयनगर पुलिस को मुखबिर से एक सूचना मिली थी। इसपर 14 दिसंबर को बस क्रमांक एमपी 09 एक्यू1300 को रोका गया था। इस बस पर सलूजा लिखा हुआ था। यह बस बंगाली चौराहा से रेडीसन चौराहा की ओर आ रही थी। तलाशी में बस की डिक्की में अंग्रेजी में JIV 18 INSECTICIDE का लेवल लगे हुए कार्टून बॉक्स भरे हुए मिले। इसमें अंग्रेजी शराब पाई गई। कब्जे से 90 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (कुल 777.6 लीटर) बरामद की गई। इसकी कीमत लगभग 7 लाख 50 हजार/- रुपए बताई गई है। बस को जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

पहला टीडीआर 40 लाख रुपए में बिका, बिल्डर ने खरीदा

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● शहर में बड़ी संख्या में आने वाले दिनों में मास्टर प्लान की सड़कों के तहत बाधक मकान तोड़े जाएंगे और कई तो तोड़े भी जा चुके हैं। ऐसे मकान मालिकों के लिए एक राहतभरी खबर है कि शहर में राज्य सरकारी की टीडीआर ((ट्रांसफर आफ डेवलपमेंट राइट्स)) पॉलिसी के तहत नगर निगम द्वारा किए जाने वाला टीडीआर बिकना शुरू हो गए हैं। रविवार को हुई बैठक में निगम के आयुक्त दिलीप कुमार यादव के द्वारा मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई की इंदौर में पहला टीडीआर बिक गया है।

इंदौर नगर निगम के द्वारा वर्ष 2017 में महू नाका चौराहा से लेकर टोरी कॉर्नर तक सड़क का निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य किया गया था। इस कार्य के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मालिकी की जमीन पर बने हुए मकान और दुकान तोड़े गए थे। इस समय निगम के द्वारा इन नागरिकों को उनके तोड़े गए निर्माण के बदले में टीडीआर का प्रमाण पत्र देने का वादा किया गया था। इस वादे को राज्य सरकार का टीडीआर एक्ट आने के बाद वर्ष 2024 में जाकर पूरा किया गया। इस सड़क पर साधना जैन का 1000 स्क्वेयर फीट का निर्माण तोड़ा गया था जिसके लिए उन्हें टीडीआर सर्टिफिकेट जारी किया गया। यह सर्टिफिकेट उनके द्वारा वसु झंवर को विक्रय किया गया है। बिल्डर अतुल झंवर ने बताया कि भुरी टेकरी पर बिल्डिंग मोर्या हिल क्रेस्ट पर अतिरिक्त निर्माण की अनुमति के लिए यह सर्टिफिकेट खरीदा गया है। इस टीडीआर सर्टिफिकेट को खरीदने के कारण 0.37 का अतिरिक्त एफएआर मिल सका है। उन्होंने कहा कि यदि नियमों में संशोधन सही तरीके से हो जाए तो हमें 0.5 का अतिरिक्त फिर मिल जाता। झंवर के द्वारा यह टीडीआर खरीदने के बाद अपने भवन का अतिरिक्त निर्माण की अनुमति के साथ वाला नक्शा मंजूरी के लिए इंदौर नगर निगम में लगाया गया। इंदौर। सरकार की महत्वपूर्ण रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) अंतर्गत विजय नगर इंदौर स्थित 33/11 केवी के कुल 21 एमवीए क्षमता के सब स्टेशन पर आंतरिक भाग में नए पैंथर कंडक्टर लगाकर क्षमता का विस्तार किया गया। इस नवीन अत्याधुनिक कार्य से भविष्य की ज्यादा बिजली मांग की पूर्ति आसान हो सकेगी।

एक हजार फीट का मकान तोड़ा गया

चोइथराम ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों की जल्द शुरू होगी जांच

हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व ट्रस्टियों की सभी आपत्तियां, कहा-आरोप प्रथम दृष्टया कार्रवाई और सुनवाई योग्य

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● चोइथराम चेरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी 21 हजार करोड़ की संपत्तियों की जांच अब जल्द शुरू हो होगी। दरअसल, रजिस्ट्रार की जांच के खिलाफ लगी याचिका खारिज के बाद अब जांच का रास्ता साफ हो गया है।

हालांकि, इस जांच में काफी समय लग सकता है क्योंकि CCT, चोइथराम इंटरनेशनल फाउंडेशन से संबद्ध है। हालांकि जांच में दस्तावेजी पेचीदगियां रहेंगी लेकिन पूरी होने के बाद संपत्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मामले हाईकोर्ट ने पूर्व ट्रस्टियों की सभी आपत्तियों को खारिज कर कहा है कि कहीं भी कार्यरत ट्रस्टी को आवेदन देने से नहीं रोका है। किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में लगाए आरोप प्रथम दृष्टया कार्रवाई और सुनवाई योग्य कारण प्रस्तुत करते हैं। चोइथराम इंटरनेशनल फाउंडेशन की ट्रस्ट डीड की व्याख्या का मुद्दा विचारणीय नहीं है। इसे अंतिम सुनवाई में देखा जा सकता है। कोर्ट ने पगरानी का नाम शिकायत से हटाने की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी कि CCT का ट्रस्टी होने के कारण उन्हें पार्टी से हटाने का आधार नहीं है। अब जांच में सच्चाई और तथ्य खास रहेंगे जिन पर आगे की कार्यवाही पर विचार होगा।

ट्रस्टी का शिकायत करना विधि सम्मत-मोतियानी के एडवोकेट अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद स्पष्ट है कि कार्यवाही एमपी पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1951 की धारा 26 के तहत पूरी तरह वैध और बनाए रखने योग्य है।

एक कार्यकारी ट्रस्टी द्वारा शिकायत दायर करना विधि सम्मत है। आरोप गंभीर हैं और रजिस्ट्रार को अपनी वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। विदेशी संपत्ति का तर्क प्रारंभिक जांच को नहीं रोकता। इस आदेश के बाद अब मामला धारा 26 और 27 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा आगे बढ़ेगा और आवश्यक होने पर विस्तृत सुनवाई के लिए जिला कोर्ट भेजा जा सकता है। ट्रस्ट संपत्तियों की पारदर्शिता और संरक्षण की दिशा में यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अब रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट शिकायत के आधार पर मामले और CIF की संपत्तियों की जांच कर पाएंगे। मामले में जिला कोर्ट को कार्रवाई के लिए भी भेज सकेंगे।

रजिस्ट्रार ने खारिज किया था आवेदन-मोतियानी की याचिका के पहले इसके खिलाफ पूर्व ट्रस्टियों ने रजिस्ट्रार को शिकायत खारिज करने का आवेदन दिया था। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन खारिज करने पर हाईकोर्ट में केस दायर किया था।

इसमें कहा था कि मोतियानी ट्रस्टी हैं और वे आवेदन नहीं दे सकते। CIF का ट्रस्ट जर्सी (अमेरिका) में रजिस्टर्ड है, इसलिए उसका परीक्षण सिर्फ वहीं की अदालत कर सकती है। रजिस्ट्रार को सुनवाई का अधिकार नहीं है।

1972 से इंदौर में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का संचालन

चोइथराम चेरिटेबल ट्रस्ट 1972 से इंदौर में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल संचालित कर रहा है। साथ ही सालों से अपनी वैधानिक फंडिंग को लेकर संघर्ष कर रहा था। ट्रस्ट के संस्थापक ठाकुरदास चोइथराम पगारानी ने विदेश में चोइथराम इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना ट्रस्टों को वित्तीय सहायता देने के लिए की थी।
शिकायत के अनुसार CIF के फंड और निवेश अरबों रुपए के हैं। इनमें CCT का लगभग एक-चौथाई (21,000 करोड़ अनुमानित) हिस्सा बताया है। CCT के चेयरमैन एवं मैनेजिंग ट्रस्टी सतीश मोतीयानी ने आरोप लगाया कि यह राशि कभी धर्मार्थ तक नहीं पहुंचाई गई।
4 व्यक्तियों लेखराज पगारानी, किशोर पगारानी, रमेश थानवानी और दयाल दतवानी ने अपने CCT के ट्रस्टी/पूर्व ट्रस्टी के पद पर रहते हुए CIF से संबंधित सूचनाएं और और महत्वपूर्ण ट्रेडमार्क विदेशी कंपनियों में दर्ज कराए हैं।
इन चारों ने इंदौर के रजिस्ट्रार, लोक न्यास द्वारा की जा रही कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
उनका दावा था कि यह मामला विदेशी संपत्तियों से जुड़ा होने के कारण रजिस्ट्रार की सीमा से बाहर है और कार्यवाही अमान्य है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर के विस्तृत आदेश में इन सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक : **अक्षय तिवारी** द्वारा मेसर्स डी.बी. कार्प लिमि. 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड़, इंदौर (मप्र)- 452008 से मुद्रित एवं 5/6, नार्थ राजमोहल्ला (गुरूद्वारे के सामने), इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। **आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650**
सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र केवल इंदौर रहेगा। समाचार पत्र में व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित खबर एवं आलेख के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।